आर्थिक समीक्षा

2024-25

मुख्य विशेषताएं

सत्यमेव जयते
Government of India

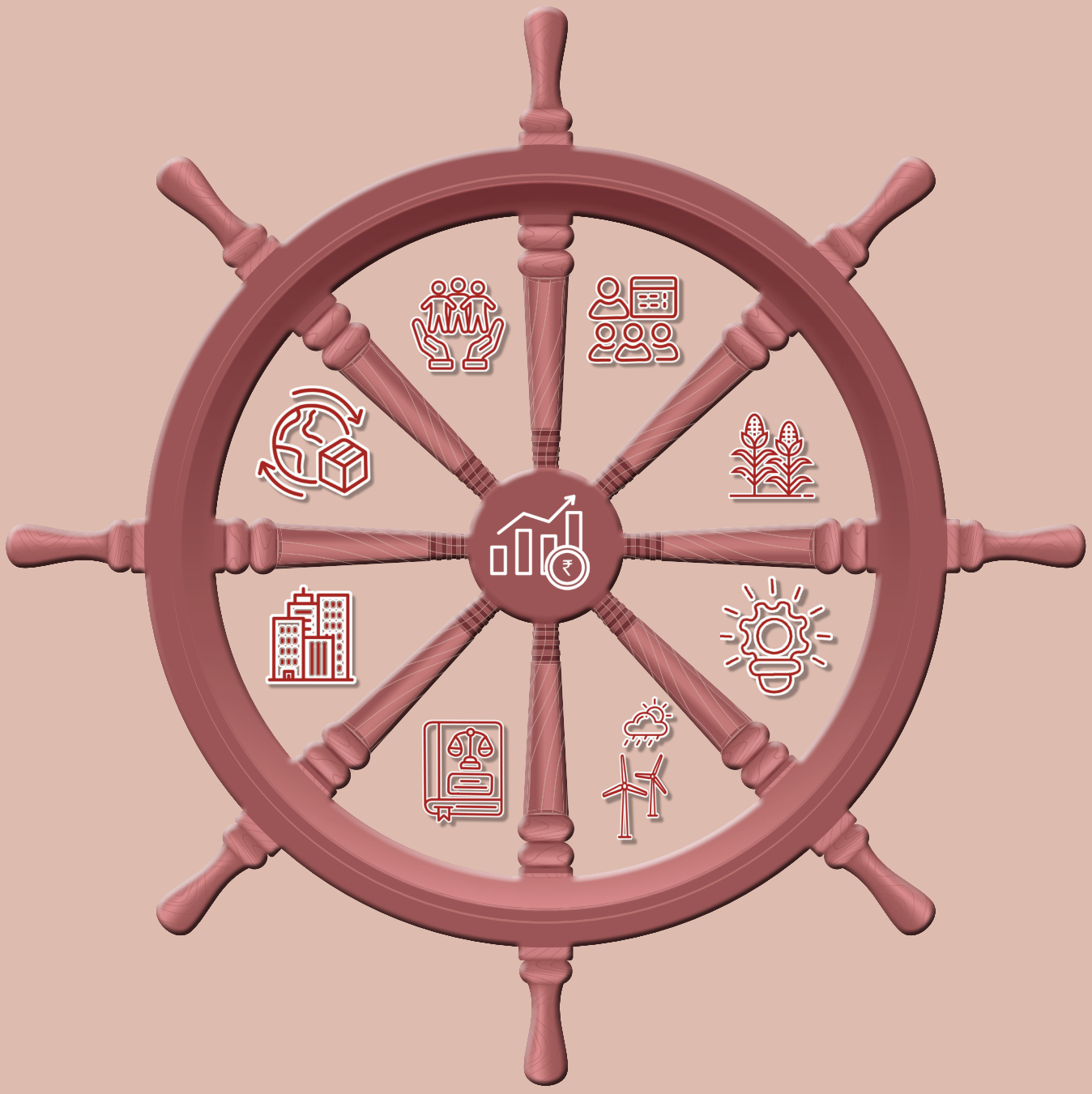

आर्थिक समीक्षा 2024-25
मुख्य बातें

आर्थिक समीक्षा 2024-25 की 'मुख्य बातें' (हाइलाइट्स) दस्तावेज 30 पृष्ठों में चार्ट, इन्फोग्राफिक्स और न्यूनतम पाठ का उपयोग करके तेरह अध्यायों में से प्रत्येक के मुख्य पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह दस्तावेज समीक्षा का एक आकर्षक और आसानी से पढ़ने योग्य सिंहावलोकन प्रदान करता है, जो पाठकों को अधिक व्यापक समझ के लिए इसकी अंतर्वस्तु का गहन विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य पाठकों के बीच जिज्ञासा तथा अधिक अन्वेषण संबंधी भाव को बढ़ावा देते हुए, जटिल डेटा को सुलभ और प्रासंगिक बनाना है, चाहे वे नीति प्रणेता हों, छात्र हों या पेशेवर हों।

वी. अनंत नागेश्वरन
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

1.	अर्थव्यवस्था की स्थिति: पुन: तेज़ गति की ओर	03
2.	मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास: अन्योन्याश्रयी संबंध	06
3.	बाह्य क्षेत्र: एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना	08
4.	कीमतें और मुद्रास्फीति: उतार-चढ़ाव को समझना	11
5.	मध्यम अवधि का परिदृश्य: गैर-विनियमन से विकास को बढ़ावा	13
6.	निवेश और अवसंरचना: अनवरत रह	14
7.	उद्योग: समग्र व्यवसायीक सुधार	18
8.	सेवा: दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियाँ	20
9.	कृषि और खाद्य प्रबंधन: भविष्य का क्षेत्र	21
10.	जलवायु और पर्यावरण: अनुकूलन की अनिवार्यता	22
11.	सामाजिक क्षेत्र: पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन	24
12.	रोजगार और कौशल विकास: अस्तित्वगत प्राथमिकताएँ	26
13.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई) युग में श्रम व्यवस्था: संकट या उत्प्रेरक?	29

1 अर्थव्यवस्था की स्थिति: पुन: तेज गति की ओर

कंट्री ग्रुप्स में स्थिर विकास की संभावना

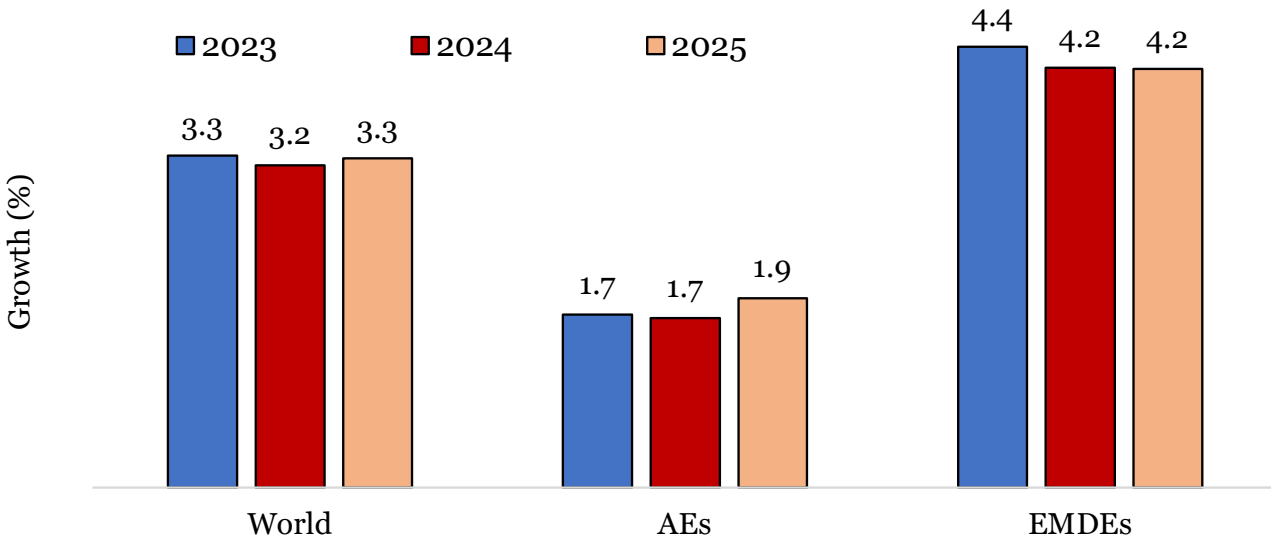

स्रोत: आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
नोट: एईएस- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, ईएमडीई- उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं

वैश्विक विनिर्माण और सेवाएं पीएमआई ट्रेंडस*

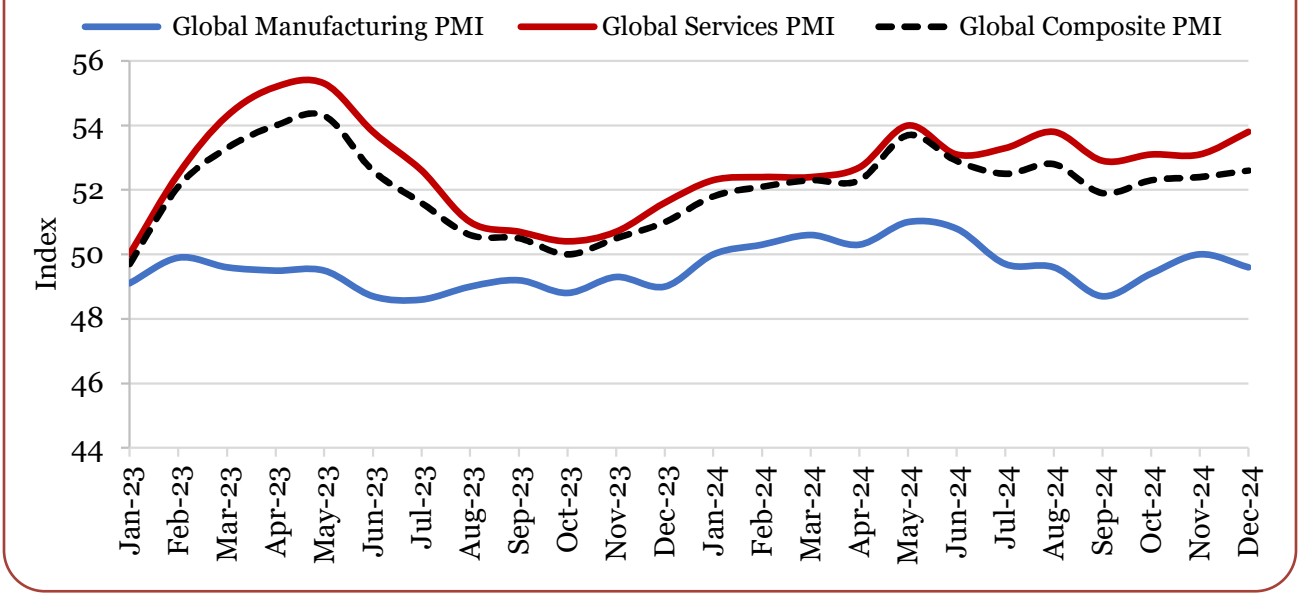

स्रोत: बुलुम्बर्ग
नोट: पीएमआई: परचेजिंग मैनेजर्स इन्डेक्स।
*सूकांक 0 से 100 के बीच बदलता रहता है, 50 से ऊपर का स्तर पिछले माह की तुलना में समग्र विद्धि दर्शाता है, तथा 50 से नीचे का स्तर समग्र कमी दर्शाता है।

वैश्विक अनिश्चितताओं में वृद्धि

2024 में विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक (डब्ल्यूटीयूआई) में वृद्धि

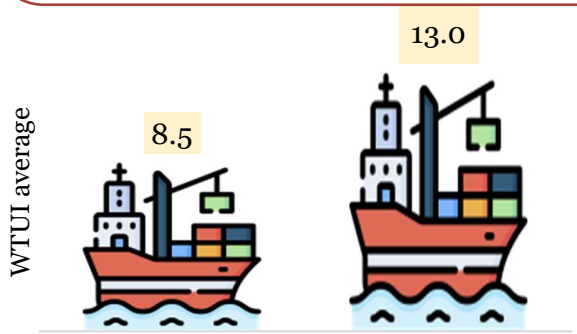

स्रोत: आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता https://www.policyuncertainty.com/gpr.html

2024 में उच्च भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक (जीपीआर)

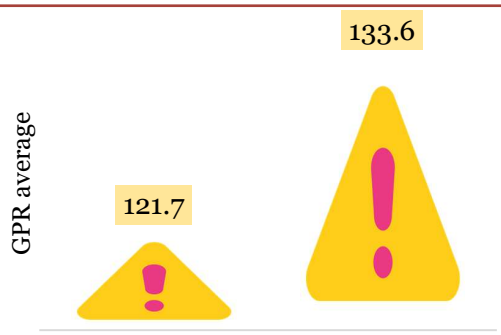

स्रोत: आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता https://worlduncertaintyindex.com/data/

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की वृद्धि दर दशकीय औसत के करीब बनी हुई है

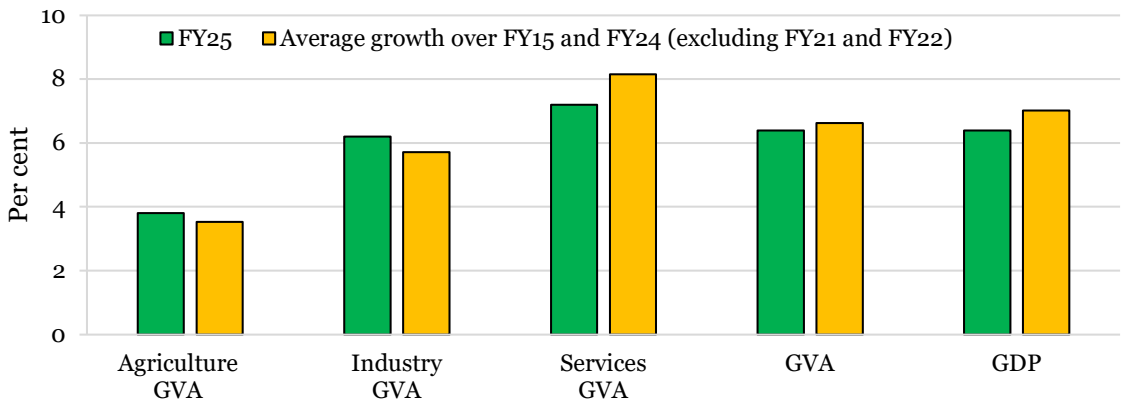

स्रोत: एमओएसपीआई, नोट: जीवीए: सकल मूल्य वर्धन: जीडीपी: सकल घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद में निवेश और उपभोग का स्थिर हिस्सा

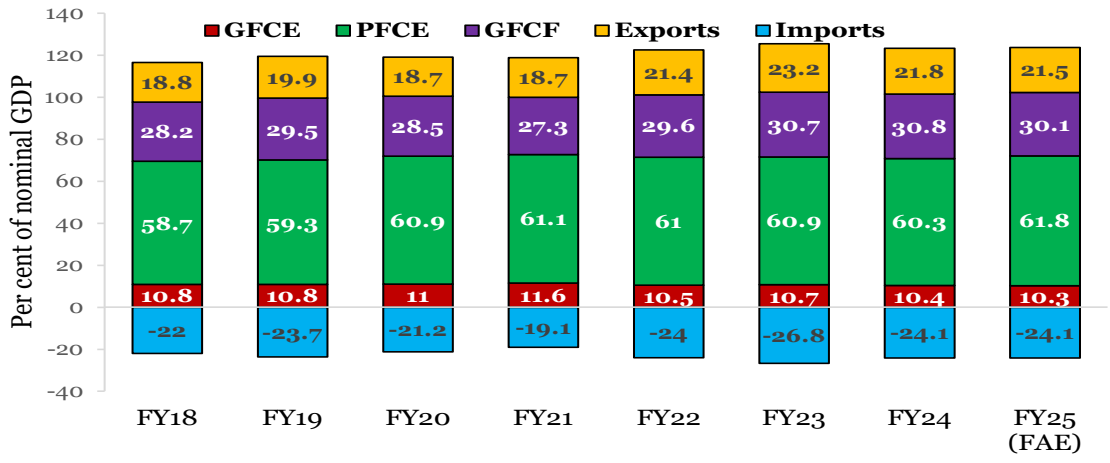

स्रोत: एमओएसपीआई,
नोट: पीएफसीई- निजी अंतिम उपभोग व्यय, जीएफसीई- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, जीएफसीएफ-सकल स्थिर पूंजी निर्माण

सुदृढ़ वाह्य क्षेत्र

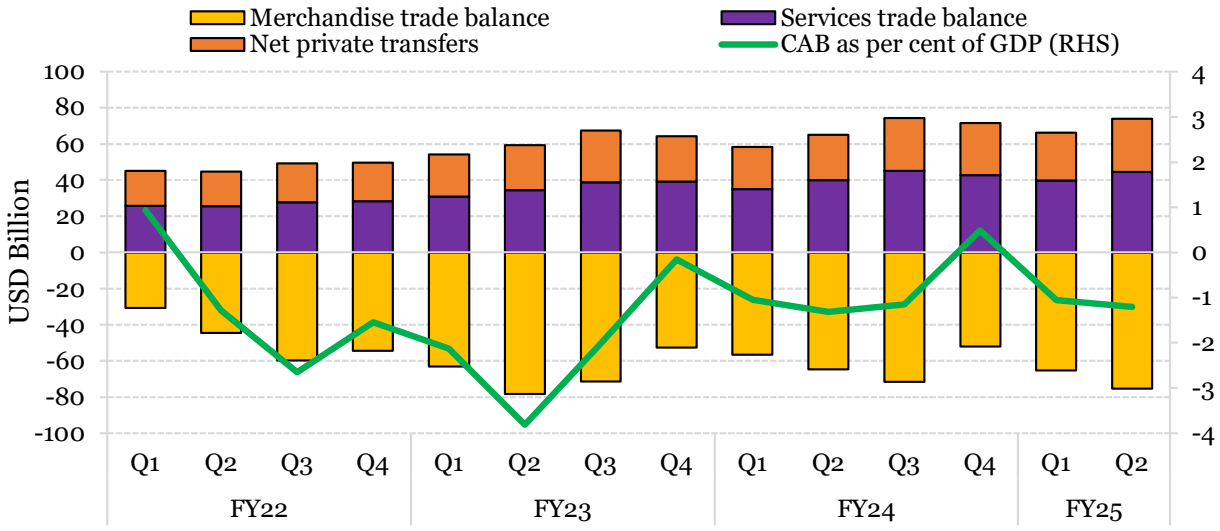

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की आरबीआई पुस्तिका
नोट: सीएबी - चालू खाता शेष

स्थिर बैंकिंग प्रणाली संकेतक

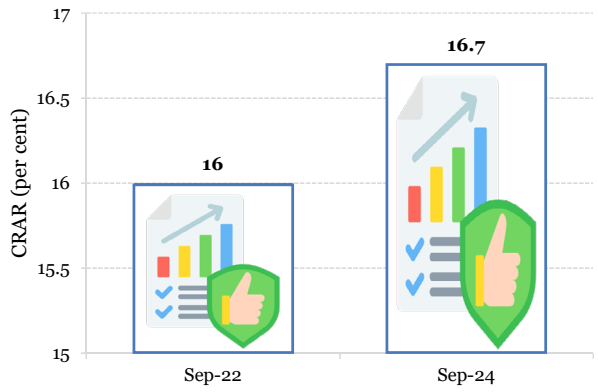

स्रोत: आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के विभिन्न संस्करण
नोट: सीआरएआर: पूंजी से जोखिम-भारित आस्ति अनुपात

आर्थिक गतिविधि में लगातार वृद्धि

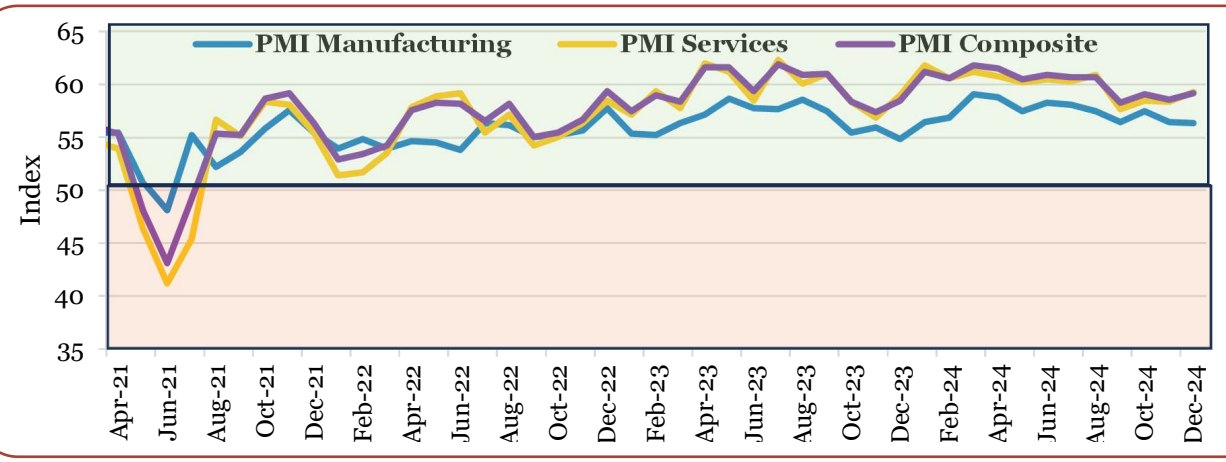

2 मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास: अन्योन्याश्रयी संबंध

बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार

एससीबी का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात (सकल अग्रिमों का%) गिरावट की ओर है

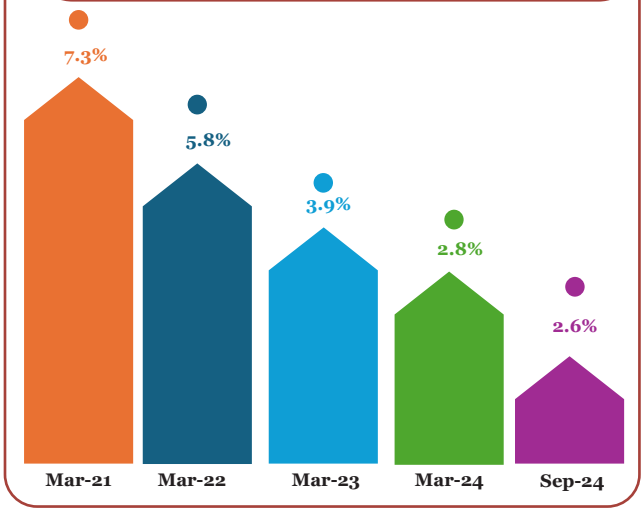

एससीबी की लाभप्रदता में सुधार परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) में वृद्धि से परिलक्षित होता है

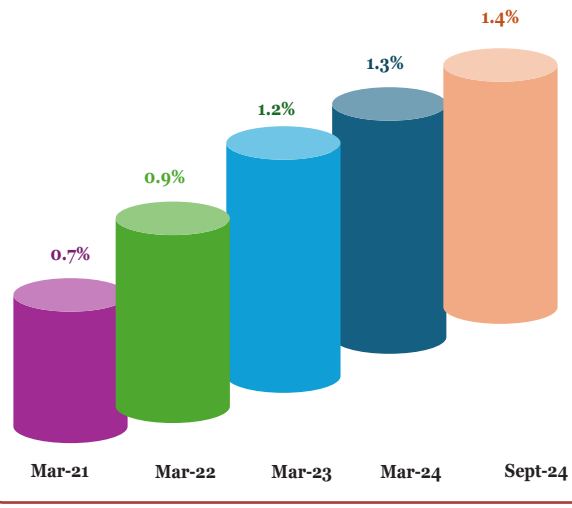

स्रोत: आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विभिन्न अंक

स्थिर बैंक ऋण

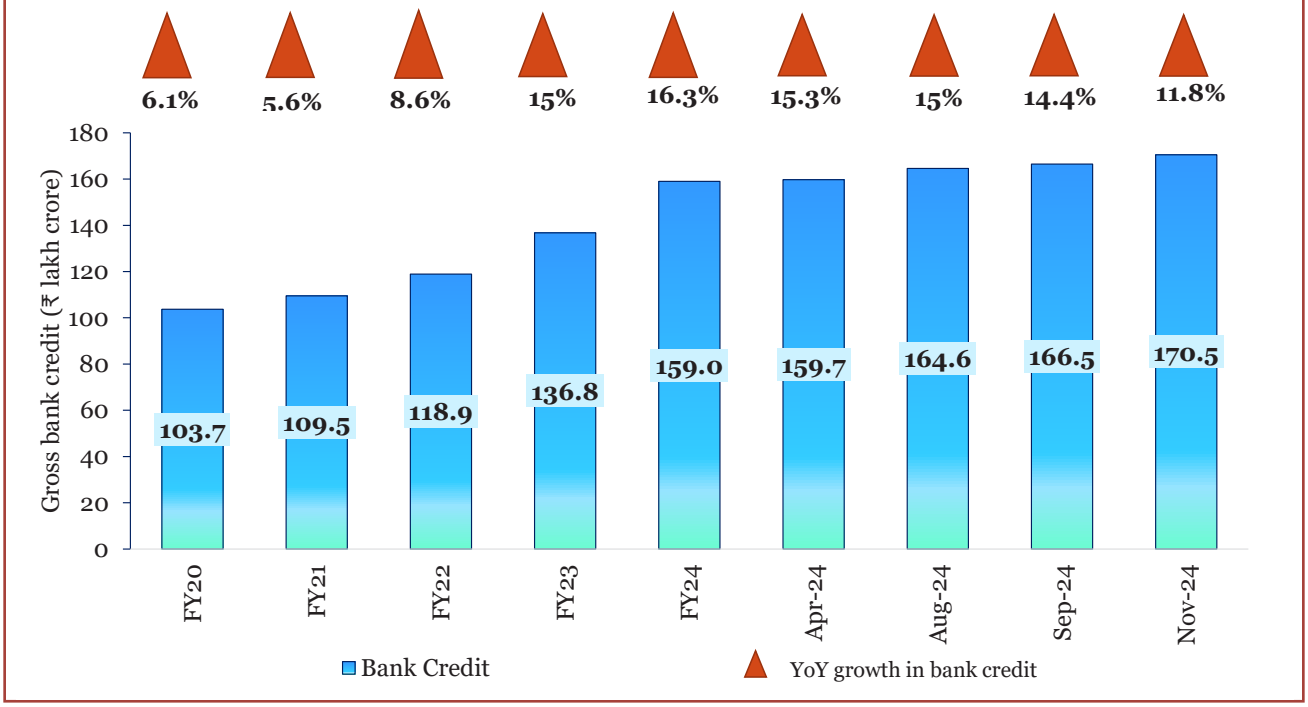

पूंजी बाजारों में विकास

अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान प्राथमिक बाजारों से 11.1 लाख करोड़ जुटाए गए, जो वित्त वर्ष 24 में जुटाई गई राशि से 5% अधिक है

दिसंबर 2024 के अंत तक डीमैट खातों की संख्या साल-दर-साल आधार पर 33% बढ़कर 18.5 करोड़ हो गई।

पूंजी बाजार का प्रदर्शन

अप्रैल-दिसंबर 2024 में आईपीओ की संख्या बढ़कर 259 हो गई, जो अप्रैल-दिसंबर 2023 (साल दर साल 32.1% की वृद्धि) में 196 थी, तथा जुटाई गई धनराशि इसी अवधि में ₹53,023 करोड़ से तीन गुना बढ़कर ₹1,53,987 करोड़ हो गई।

पूंजी बाजार का प्रदर्शन विशिष्ट म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या वित्त वर्ष 2011 में 2.9 करोड़ से दोगुनी होकर दिसंबर 2024 तक 5.6 करोड़ हो गई।

दिसंबर 2024 के अंत में भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी का अनुपात 136% रहा, जो अन्य ईएमई की तुलना में कहीं अधिक है।

पिछले तीन वर्षों में मासिक औसत सकल एसआईपी प्रवाह दोगुना से अधिक हो गया है, जो वित्त वर्ष 2012 में ₹0.10 लाख करोड़ से बढ़कर 24 दिसंबर तक ₹0.23 लाख करोड़ हो गया।

स्रोत: सेबी

ग्रामीण वित्तीय संस्थानों ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

वित्तीय समावेशन पर सरकार का विशेष महत्व

आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक में मार्च 2021 में 53.9 से सुधार होकर मार्च 2024 तक 64.2 हो गया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन

700 जिलों में 22,069 शाखाएँ

- 26 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र
- सभी शाखाओं में 14% हिस्सा (सभी बैंक)
- ग्रामीण शाखाओं में 30% हिस्सा (सभी बैंक)
- ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 92% शाखाएँ

₹ 6.6 लाख करोड़ जमा राशि

- 31.3 करोड़ राशि जमा खाते
- जमा राशि में 3.2% हिस्सा (सभी बैंक)
- जमा खातों में 13.7% हिस्सा (सभी बैंक)

₹ 4.7 लाख करोड़ अग्रिम

- 3 करोड़ ऋण खाते
- अग्रिम राशि में 2.9% हिस्सा (सभी बैंक)
- ऋण खातों में 8% हिस्सा (सभी बैंक)

3 बाह्य क्षेत्र: एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना

वैश्विक व्यापार गतिशीलता

वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता का बढ़ना

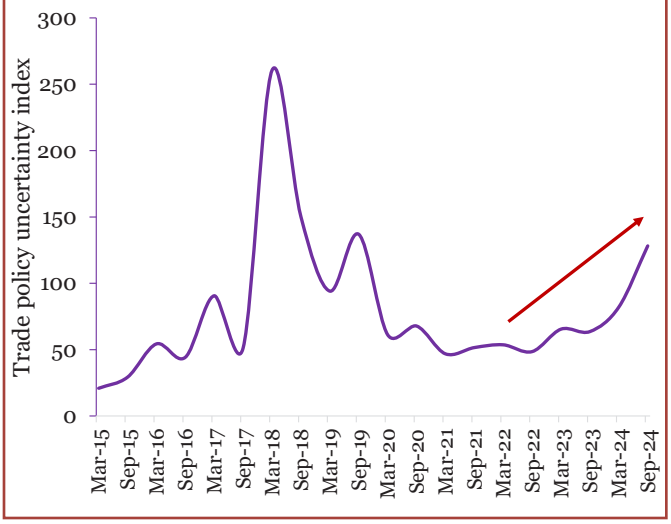

2024 में वैश्विक व्यापार में उछाल

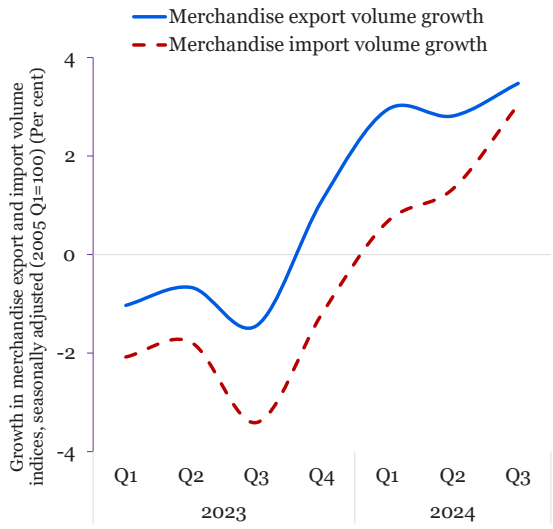

वित्त वर्ष 2025 के पहले आठ महीनों में भारत का व्यापार प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2015 के पहले नौ महीनों में व्यापारिक व्यापार घाटा बढ़ा

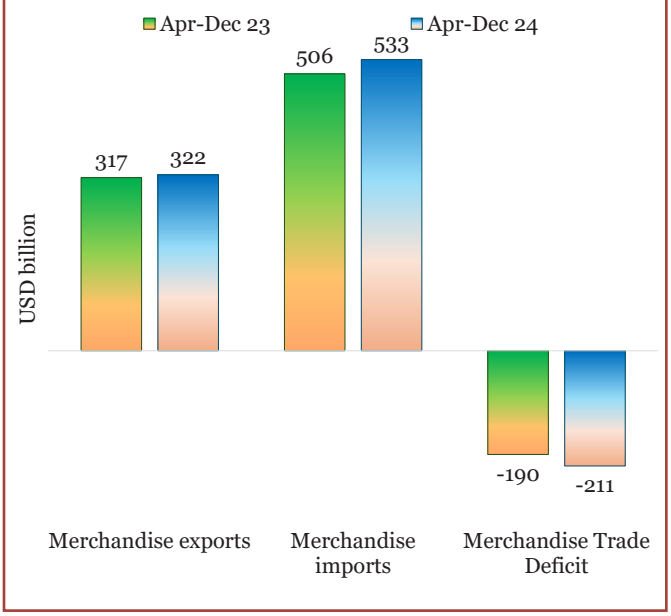

वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में गैर-पेट्रोलियम और गैर-पेट्रोलियम एवं गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात ने अच्छा प्रदर्शन किया

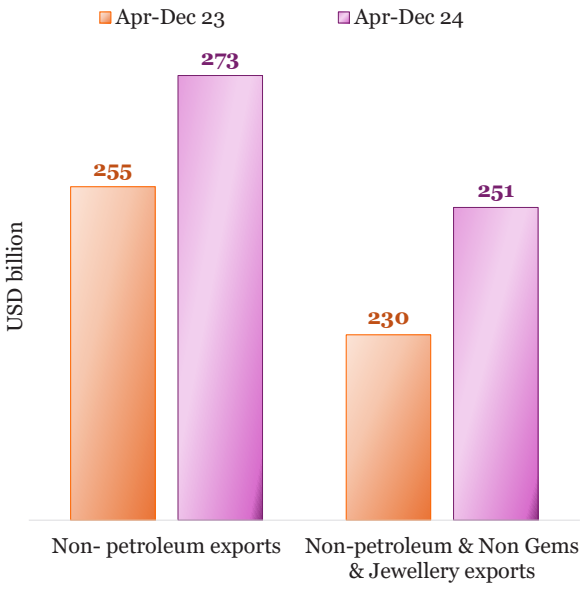

वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में सेवा व्यापार अधिशेष

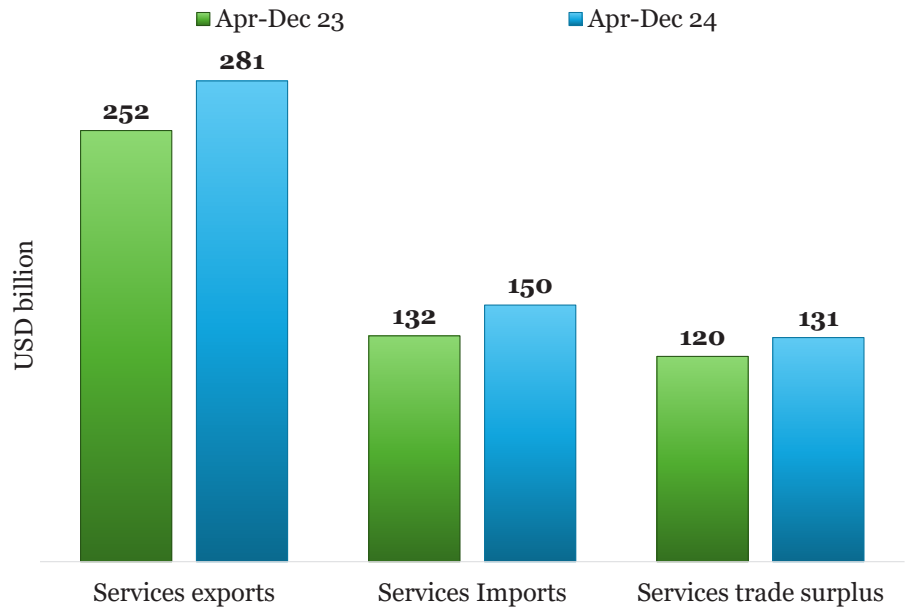

स्रोत: डीजीसीआईएस, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

- अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान व्यापारिक निर्यात में मध्यम वृद्धि, मुख्य रूप से पेट्रोलियम निर्यात के मूल्य में गिरावट के कारण जो अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट से प्रेरित है।
- मुद्रास्फीति के प्रभाव के बावजूद व्यापारिक आयात में वृद्धि घरेलू खपत में उछाल को दर्शाती है।

निर्यातकों के लिए व्यापार करने में सुगमता संबंधी पहल

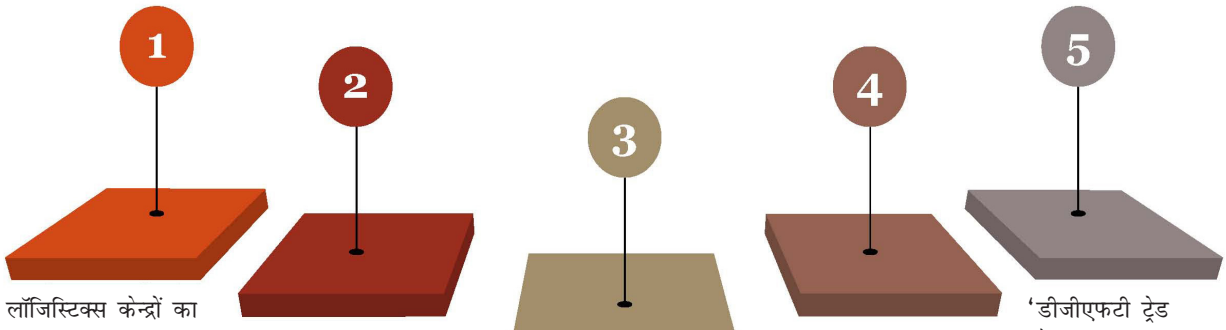

भारत ने पर्याप्त मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित करना जारी रखा है

सकल एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि; प्रत्यावर्तन लाभदायक निकास का संकेत है

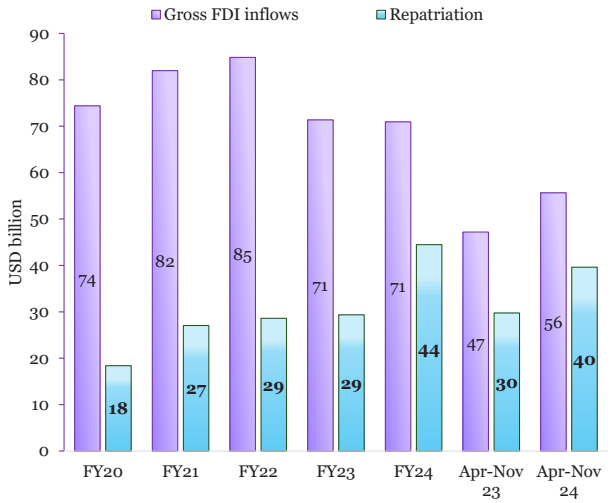

वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 19.1% हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र एफडीआई अंतर्वाह में सबसे आगे है, इसके बाद प्रौद्योगिकी, ट्रेडिंग और गैर-पारंपरिक ऊर्जा का स्थान आता है।

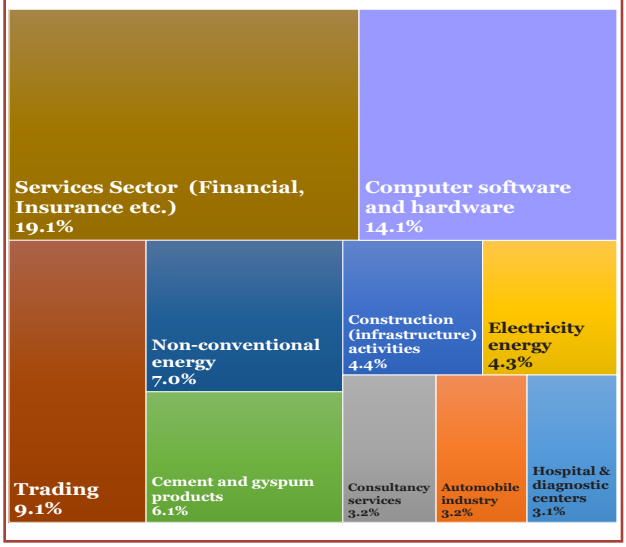

वैश्विक अस्थिरता के बीच विदेशी मुद्रा भंडार

सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 706 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर था; और 27 दिसंबर, 2024 तक 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो विदेशी ऋण का 89.9% कवर करता है।

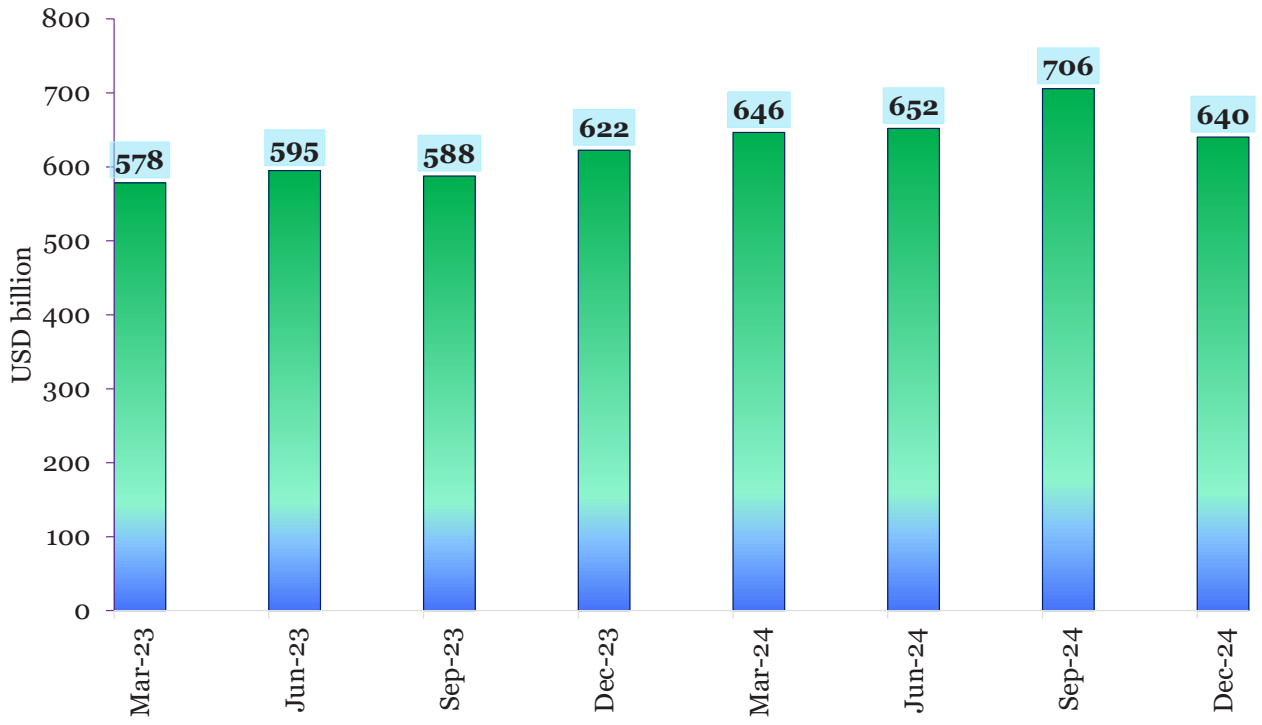

4

कीमतें और मुद्रास्फीति: उतार-चढ़ाव को समझना

कोर मुद्रास्फीति में नरमी से हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी

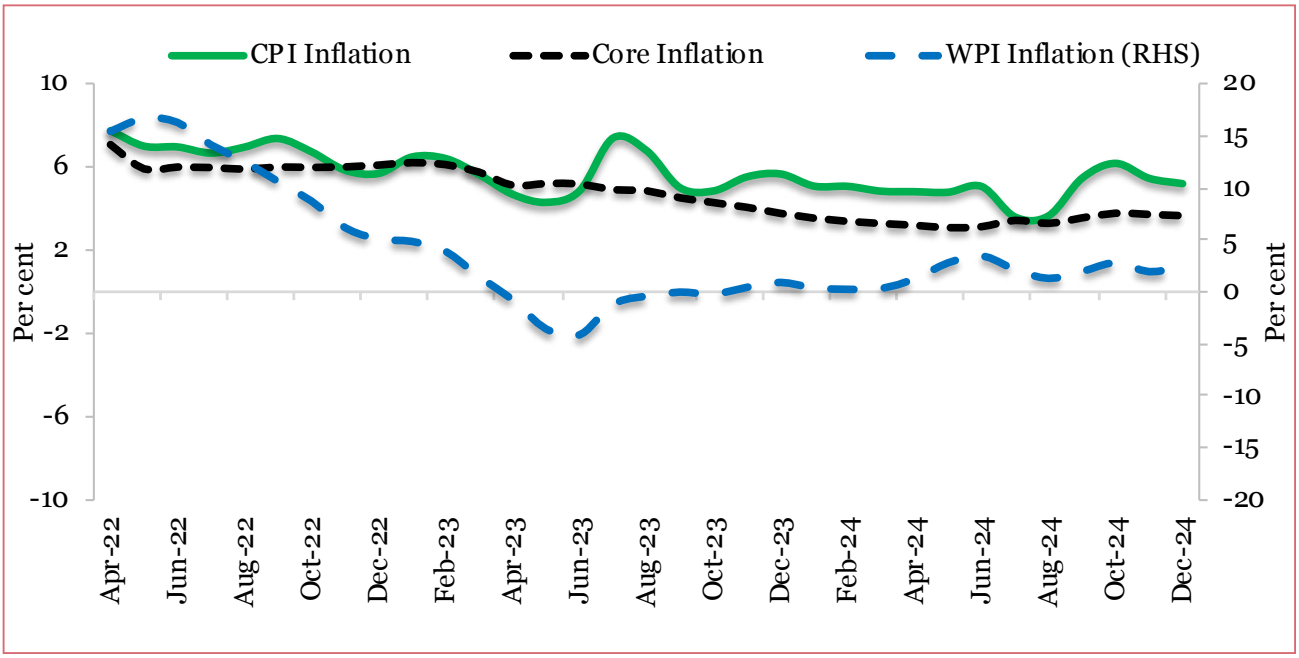

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य

कुछ खाद्य वस्तुओं के कारण होने वाली हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति

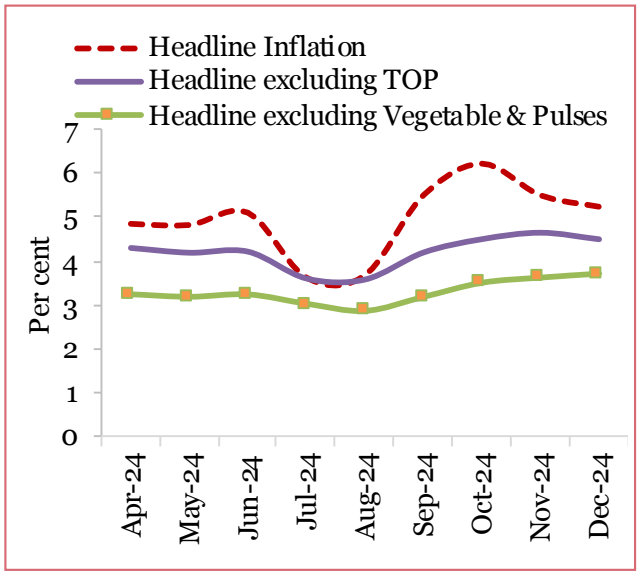

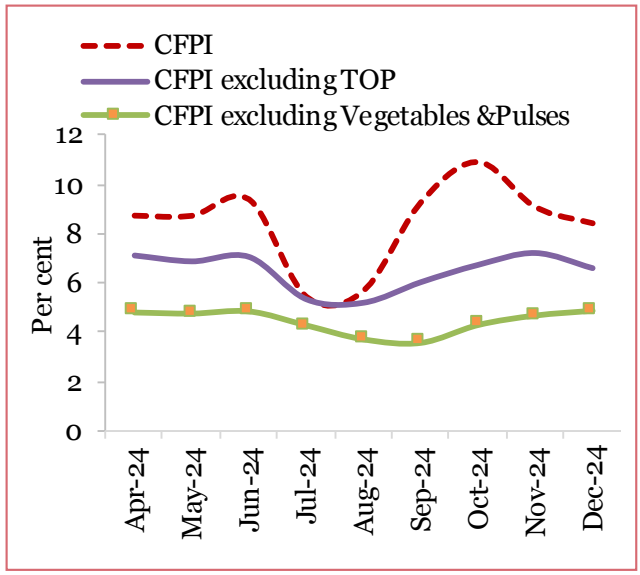

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सब्जियों की मुद्रास्फीति पर चरम मौसम स्थितियों का प्रभाव :तीन माह तक का विवरण (अप्रैल 2020-दिसम्बर 2024)

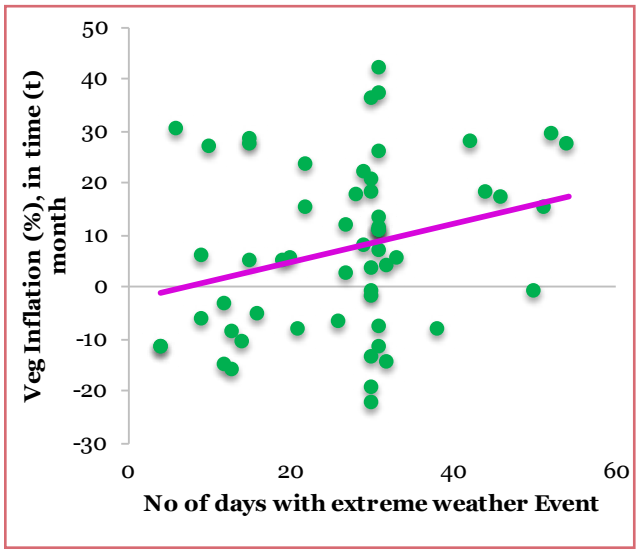

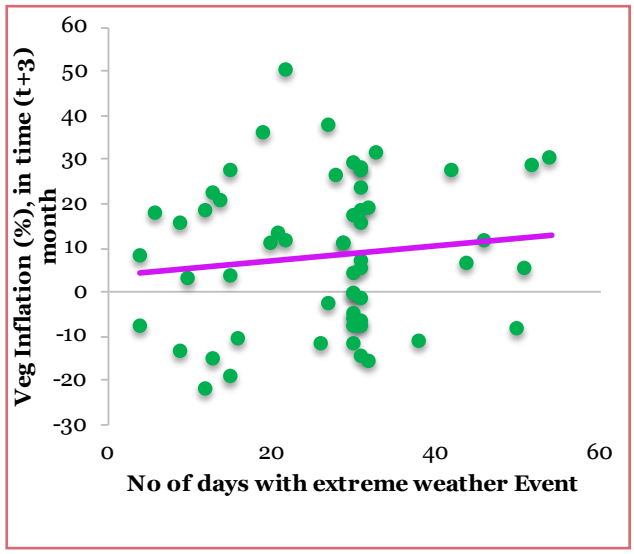

स्रोत: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के प्रशासनिक उपाए

अनाज

- गेहूं पर स्टॉक सीमाएं
- खुला बाजार बिक्री योजना: गेहूं और चावल
- भारत ब्रांड के तहत बिक्री: चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल

दालें

- शुल्क मुक्त आयात: देसी चना, तुअर, उड़द मसूर और पीली मटर
- शुल्क मुक्त आयात: देसी चना, तुअर, उड़द मसूर और पीली मटर
- स्टॉक सीमाएं: तुअर और देसी चना

सब्जियां

- प्याज और टमाटर की सब्सिडी प्राप्त बिक्री
- प्याज का बफर स्टॉक

स्रोत: विभिन्न पीआईबी रिलीज

5

मध्यम अवधि का परिदृश्य: गैर-विनियमन से विकास को बढ़ावा

विकास के घरेलु उत्प्रेरकों को गति प्रदान करना तथा व्यक्तियों और व्यवसायों की आर्थिक स्वतंत्रता

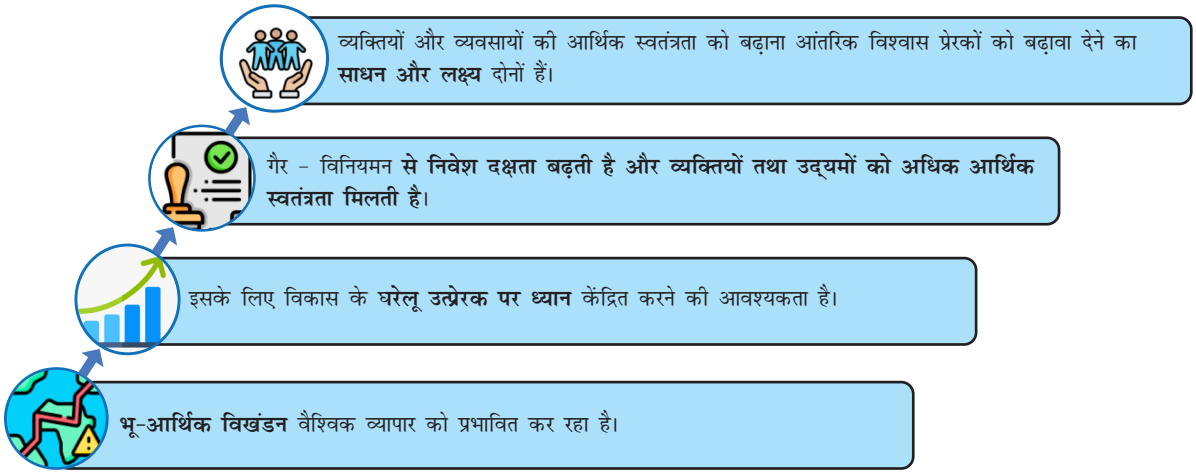

ईओडीबी-2.0-गैर विनियमन को व्यवस्थित रूप से लागू करना

चरण-1 में आगे बढ़ाया गया।

- ✓ **अनुपालन के बोझ में कमी** — व्यवसायों का समय और प्रशासनिक लागत बचाना
- ✓ **सुव्यवस्थित प्रणाली, प्रक्रिया और जानकारी** — अतिरेक को समाप्त करना, प्रक्रिया प्रवाह को स्पष्ट करना
- ✓ **डिजिटल प्रणाली, प्रक्रिया और जानकारी** — अंतक्रिया के डिजिटल साधन स्थापित करना
- ✓ **प्रदत्त प्रोत्साहन** — प्रमुख क्षेत्रों या समूहों को विशेष लाभ प्रदान करना

चरण-2 में आगे बढ़ाया जाना है।

- ☐ **मानकों और नियंत्रणों को उदार बनाना** — 'न्यूनतम आवश्यक, अधिकतम व्यवहार्य' मानदंड अपनाना
- ☐ **प्रवर्तन के लिए कानूनी रक्षोपाय निर्धारित करना** — रक्षोपाय के अनुक्रम के माध्यम से कानून की उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करना
- ☐ **प्रशुल्क या शुल्क कम करना** — उपयोगिताओं के लिए सरकार को दिए जाने वाले प्रशुल्क/शुल्क को कम करना/ हटाना
- ☐ **जोखिम-आधारित वि. नियमन का प्रयोग** — जोखिम प्रोफाइल के लिए कानूनी मानदंडों के अनुकूल, तीसरे पक्ष को शामिल करना

6 निवेश और अवसंरचना: अनवरत रहे

भौतिक कनेक्टिविटी में प्रगति

रेलवे

वंदे भारत ट्रेनों की संचयी संख्या और कोचों का विनिर्माण

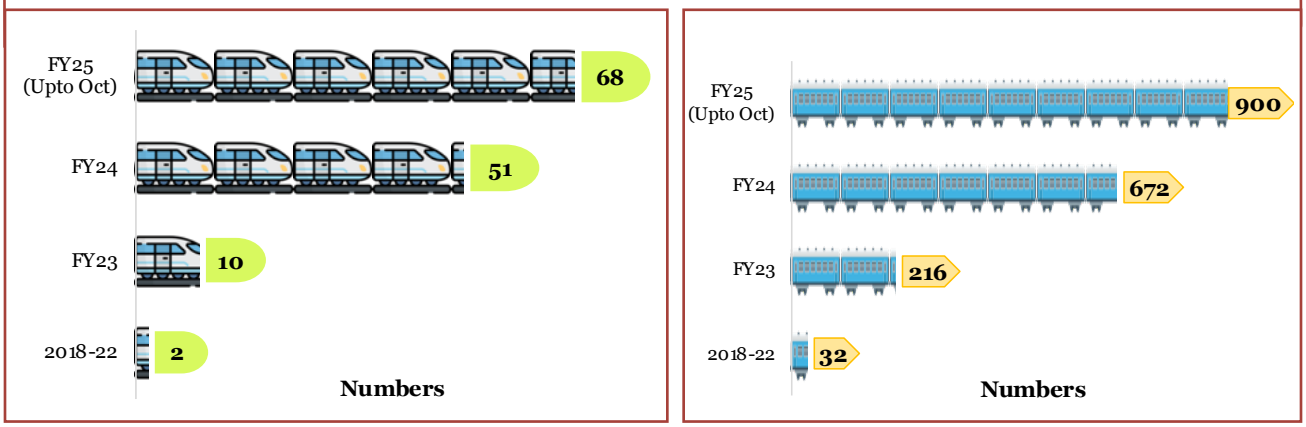

स्रोत: रेल मंत्रालय

नागर विमानन और पत्तन तथा पोत परिवहन

आरसीएस के अंतर्गत परिचालित हवाई अड्डे और मार्ग

प्रमुख पत्तनों में औसत टर्नअराउंड समय में कमी

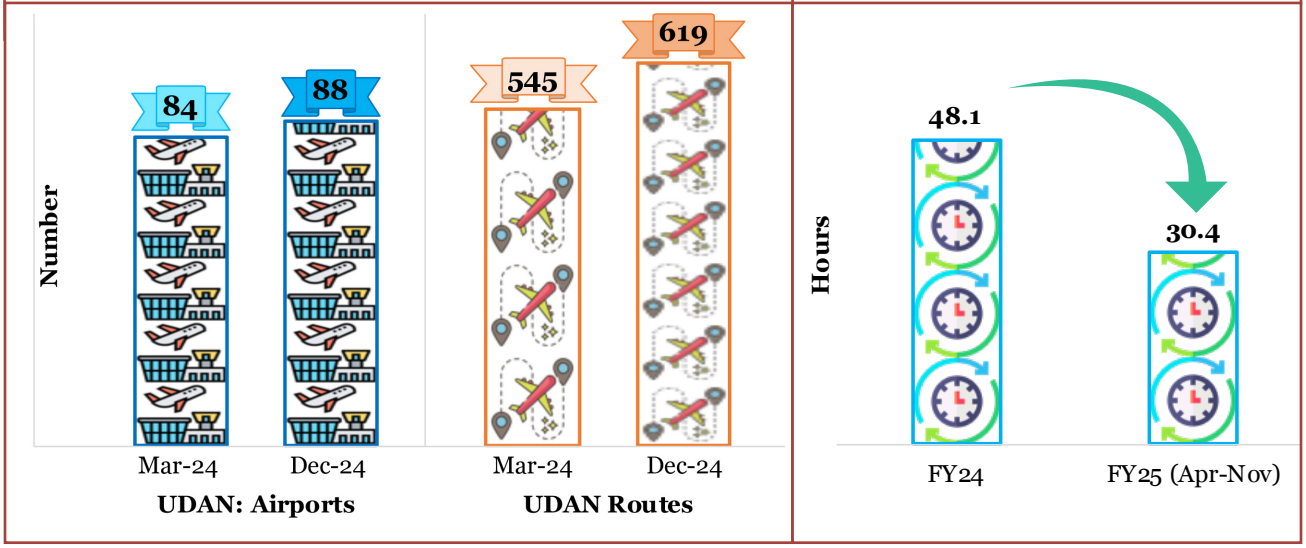

स्रोत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे और जेवी/पीपीपी हवाई अड्डे, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

विद्युत क्षेत्र

विद्युत क्षेत्र में क्षमता संवर्धन

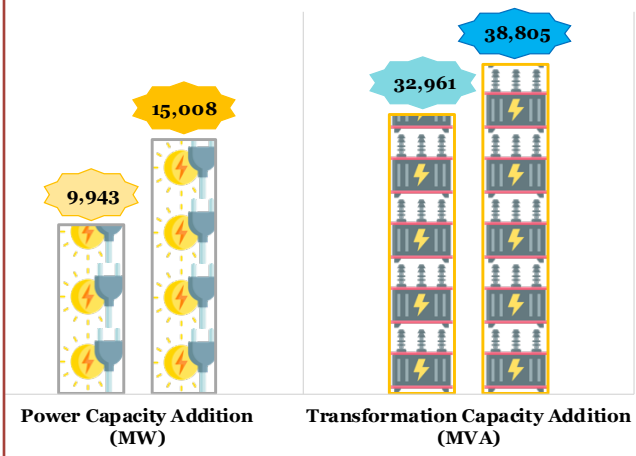

नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता

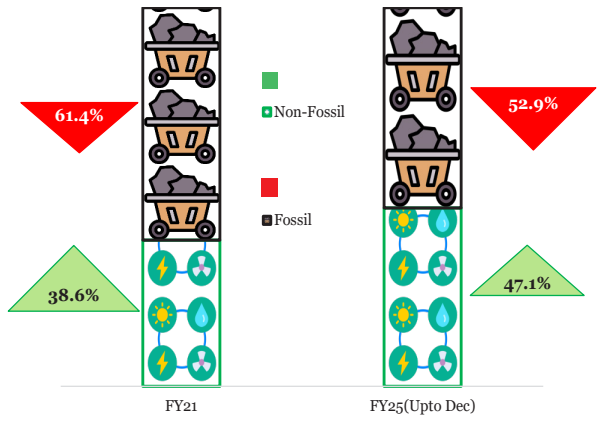

स्रोत: कार्यकारी सारांश रिपोर्ट, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

डिजिटल कनेक्टिविटी

दूरसंचार अवसंरचना में प्रगति

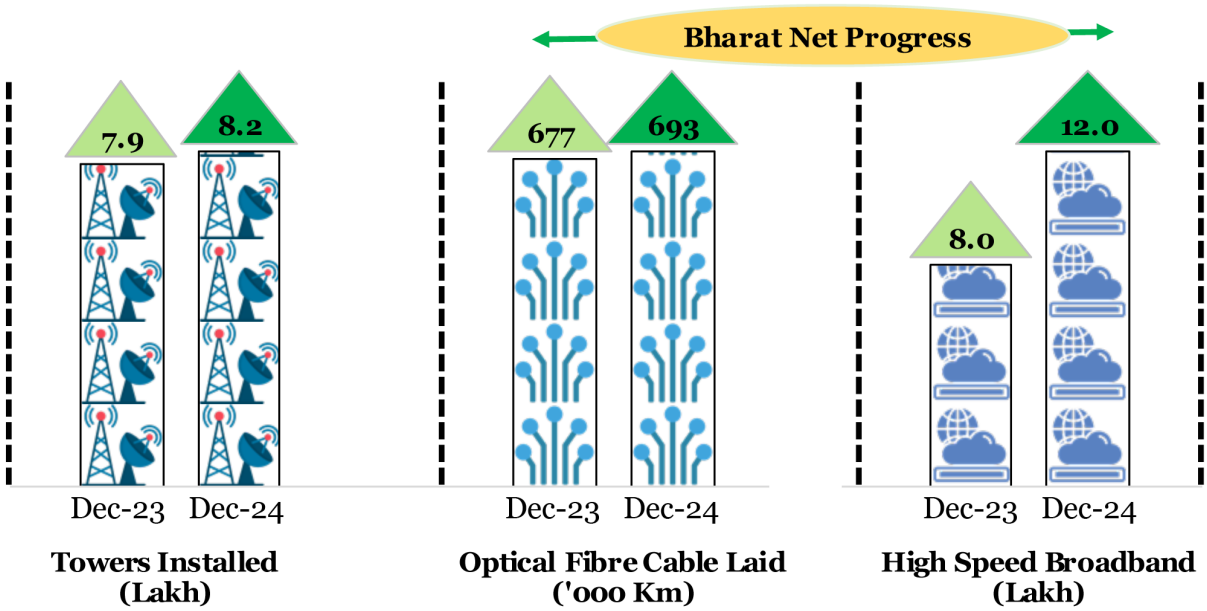

स्रोत: डिजिटल भारत निधि डैशबोर्ड, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रतिः सुरक्षित पाइप पेयजल तक पहुंच

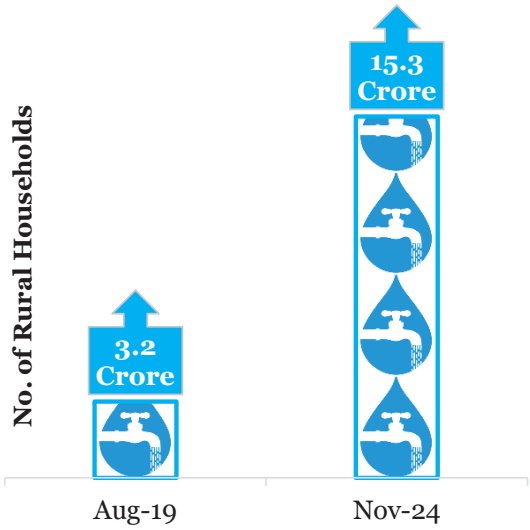

जेजेएम के अंतर्गत पूर्ण कवरेज प्राप्त करने वाले राज्यः

1. अरुणाचल प्रदेश
2. गोवा
3. हरियाणा
4. हिमाचल प्रदेश
5. गुजरात
6. पंजाब
7. तेलंगाना
8. मिजोरम

स्रोतः जलशक्ति मंत्रालय

ओडीएफ प्लस दर्जा प्राप्त करने वाले गांवों की संख्या में वृद्धि

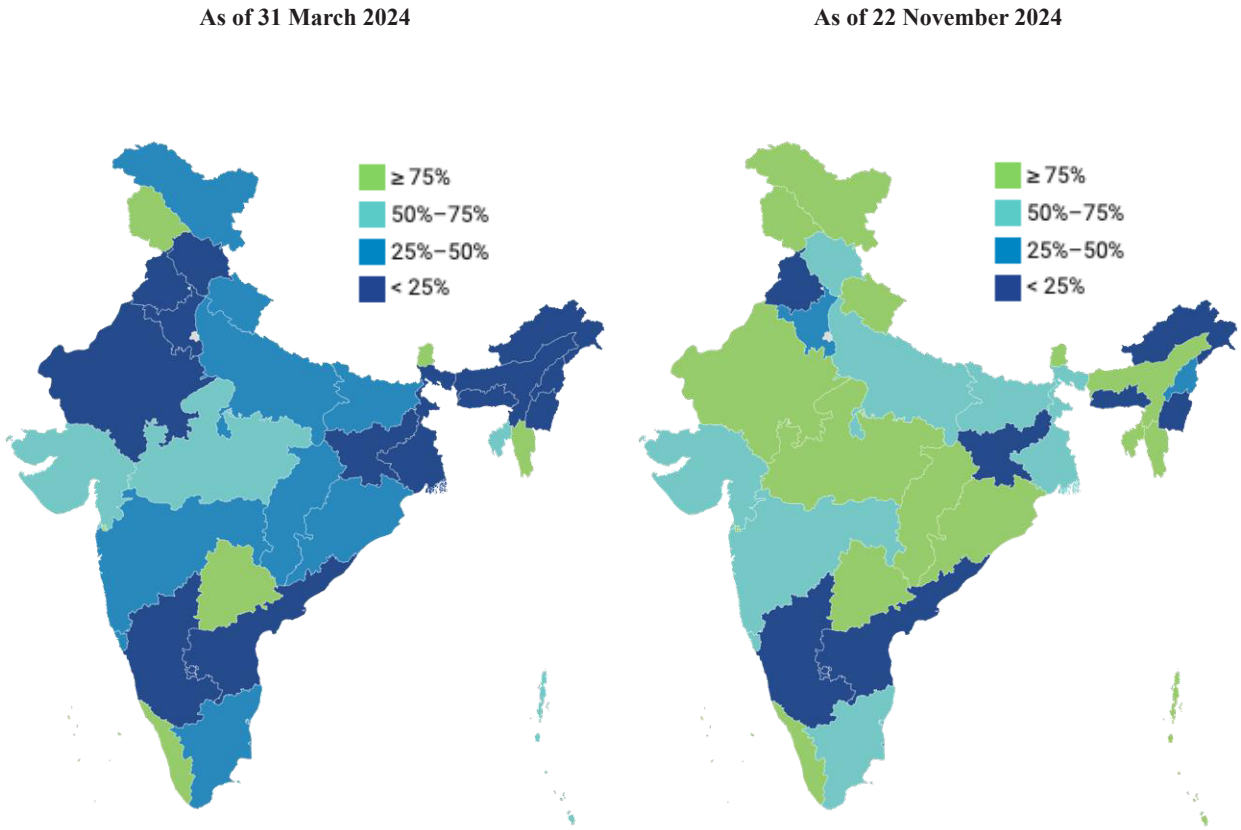

स्रोतः जल शक्ति मंत्रालय
नोटः चार्ट में ''मॉडल'' ग्राम प्रस्तुत किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत प्रगति*

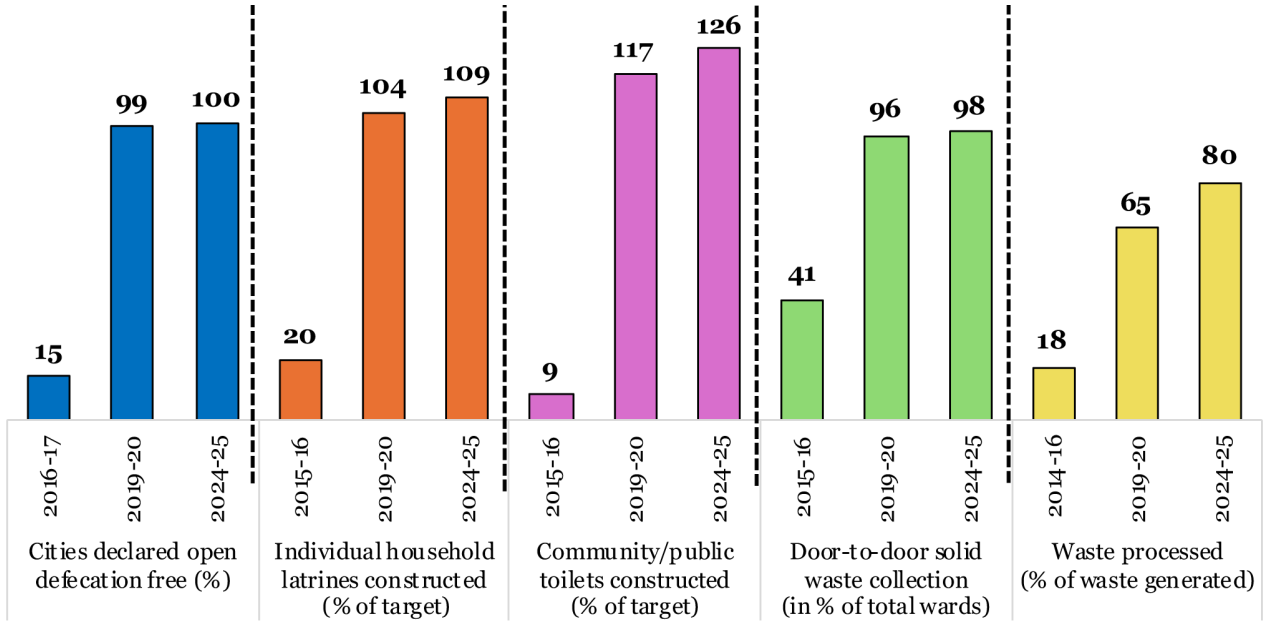

स्रोत: आवसन और शहरी कार्य मंत्रालय
*नोट: 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार

विभिन्न पहलों के अंतर्गत प्रगति

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी: 25 नवंबर 2024 तक 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है

शहरी परिवहन: मेट्रो रेल प्रणाली: वर्तमान में 23 शहरों में 1010 किलोमीटर परिचालन में है और अतिरिक्त 980 किलोमीटर निर्माणाधीन है।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल-मिशन: नल जल कवरेज 70 प्रतिशत तक बढ़ा, और सीवरेज कवरेज 62 प्रतिशत तक बढ़ा।

स्मार्ट सिटी मिशन: 13 जनवरी 2025 तक 93 प्रतिशत परियोजनाएँ पूरी हो जाएंगी।

7 उद्योग: समग्र व्यवसायिक सुधार

अर्थव्यवस्था में आशावाद

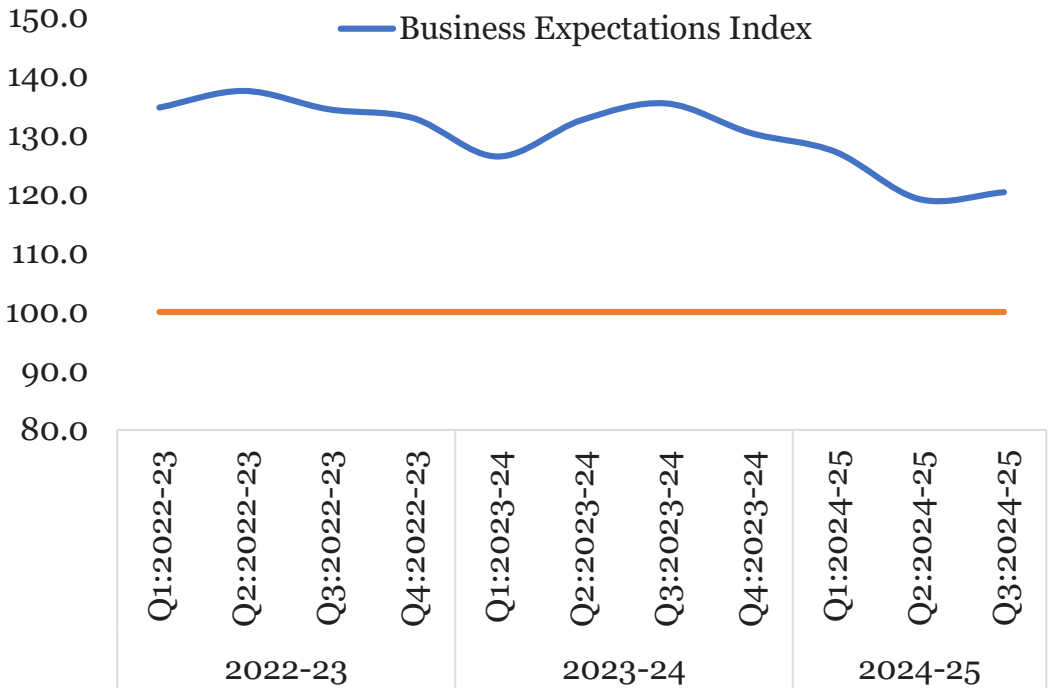

नोट: 100 से कम आशावादी 100 से अधिक निराशावादी

भारत के बुनियादी ढांचे को संवर्धित करती सीमेंट और इस्पात उत्पादन वृद्धि बढ़ता हुआ सीमेंट उत्पादन वृद्धि

बढ़ता हुआ सीमेंट उत्पादन

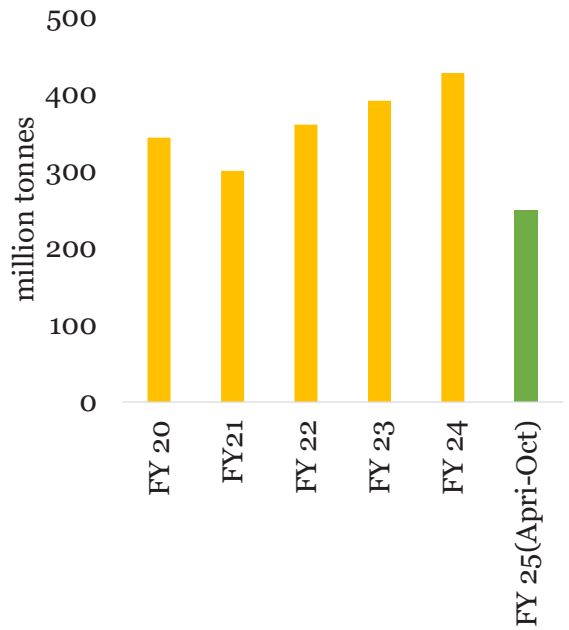

इस्पात के उत्पादन और खपत में निरंतर वृद्धि

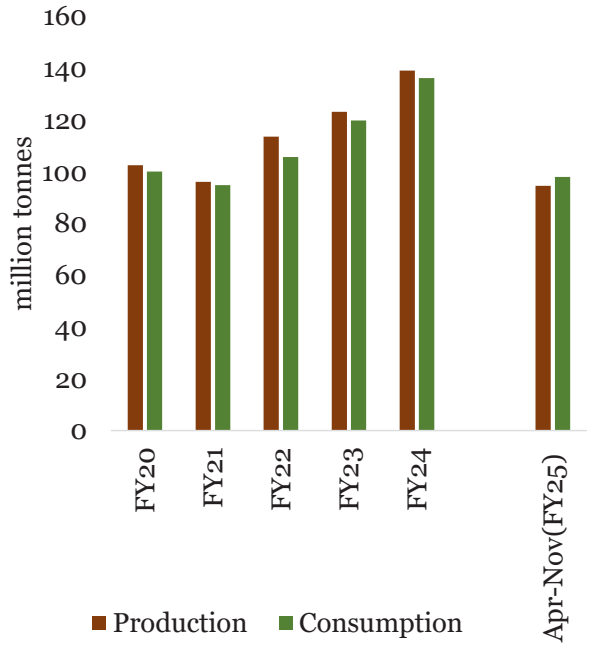

उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का प्रदर्शन

कपड़ा निर्यात में वृद्धि

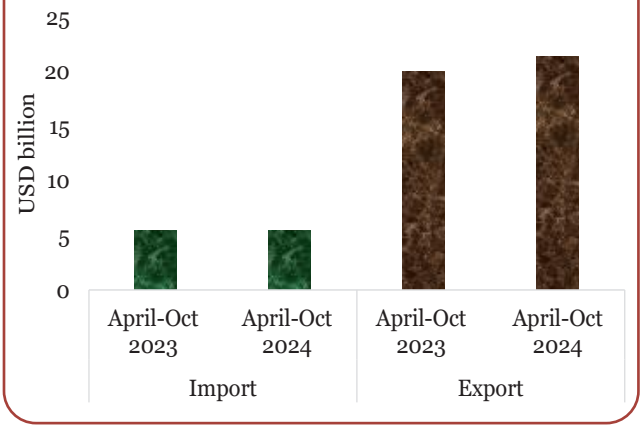

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बढ़ती गति

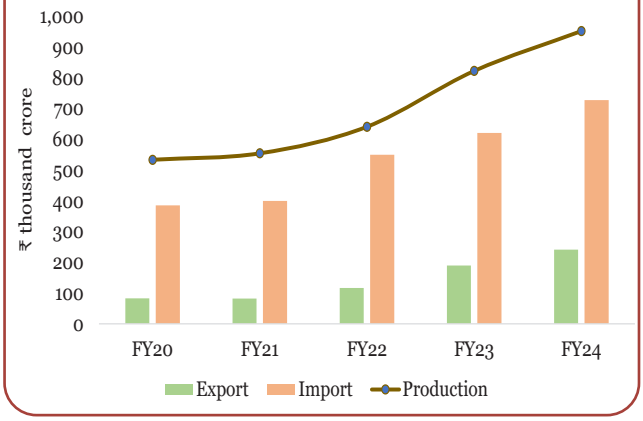

भारत में तेजी से बढ़ती बौद्धिक संपदा

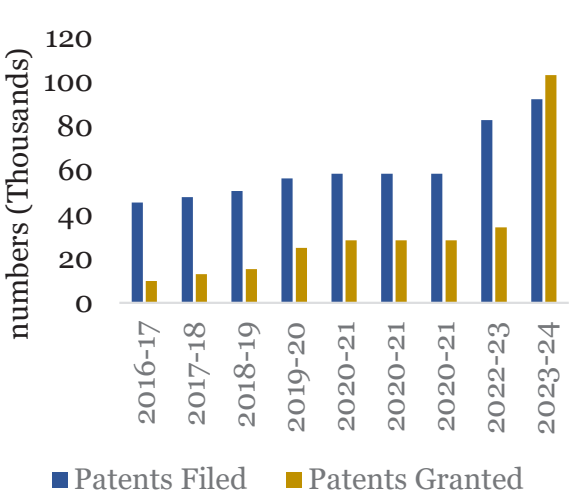

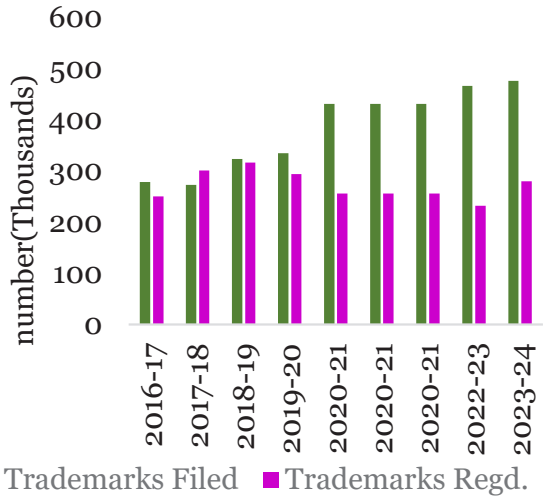

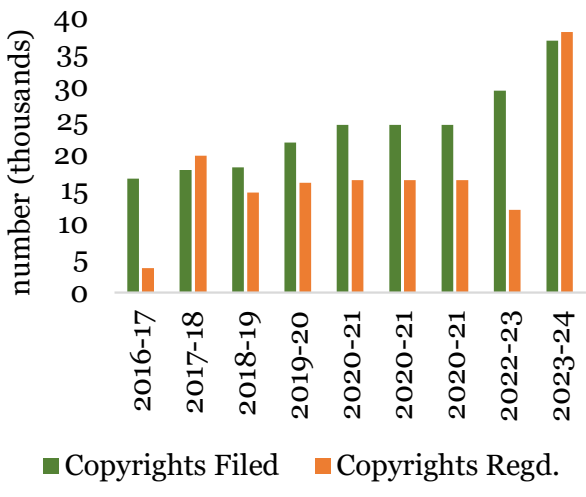

8 सेवाएं: दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतिया

जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ने का रुझान

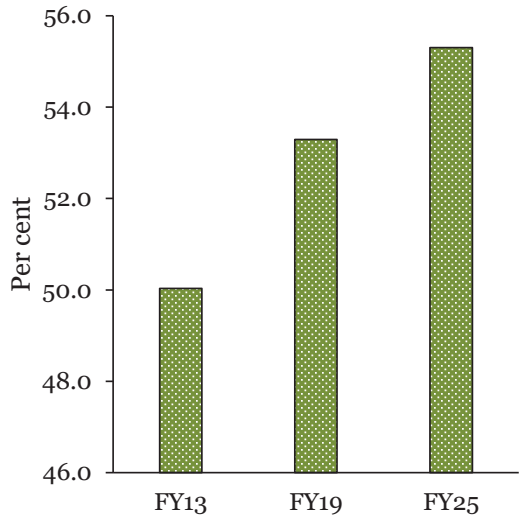

वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी

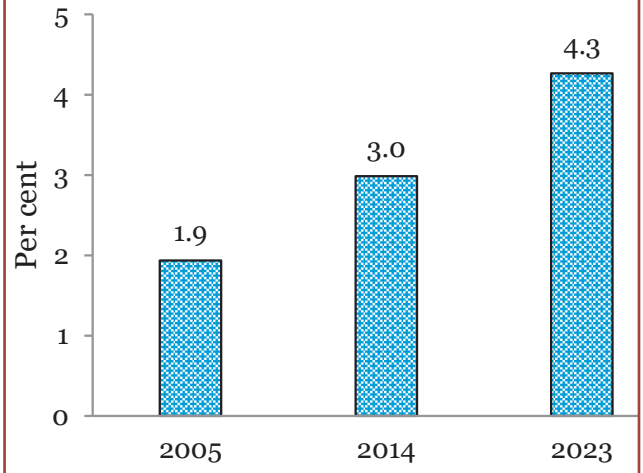

सेवाओं के लिए चुनौतियां, अवसर और भविष्य की राह

नई चुनौतियां

अपतटीय कार्य

पारंपरिक प्रशिक्षुता मॉडल को अपर्याप्त प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, भाषा बाधाओं, सूचना अंतराल और देशों में विनियामक प्रावधानों में अंतर की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है

अवसर

सेवाकरण

- अंतर्निहित सेवाओं की बढ़ती मांग
- सेवाओं और विनिर्माण में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाना
- सेवाओं में वैश्विक व्यापार की शक्ति को बढ़ाना

भविष्य की राह

नीतिगत समर्थन

डिजिटल क्रांति के परिणाम से लाभ उठाने के लिए उपयुक्त रूप से कौशल युक्त बनाना

विकास में बाधा डालने वाली जमीनी स्तर की प्रक्रियाओं और विनियमों में सुधार

9 कृषि और खाद्य प्रबंधन: भविष्य का क्षेत्र

गैर-संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी में गिरावट

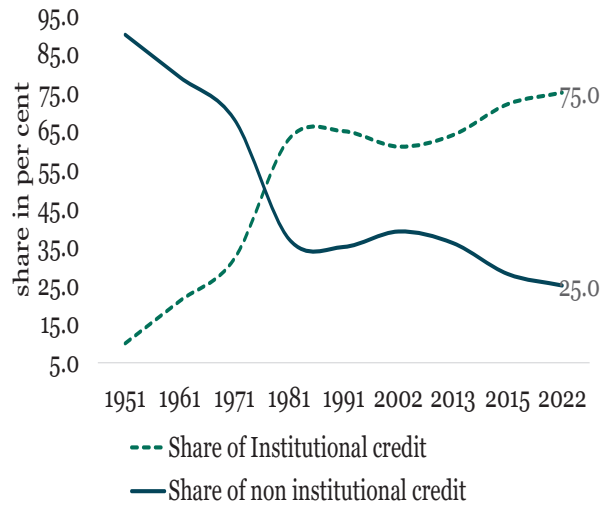

छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि (लाख करोड़ रुपये में)

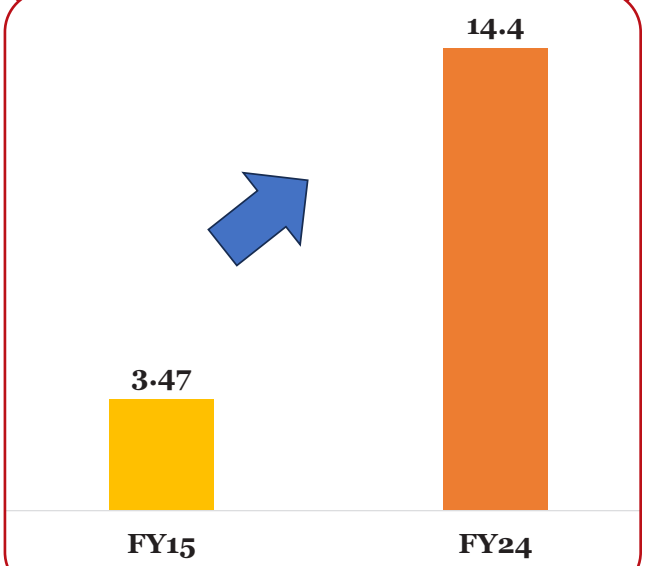

लघु सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि

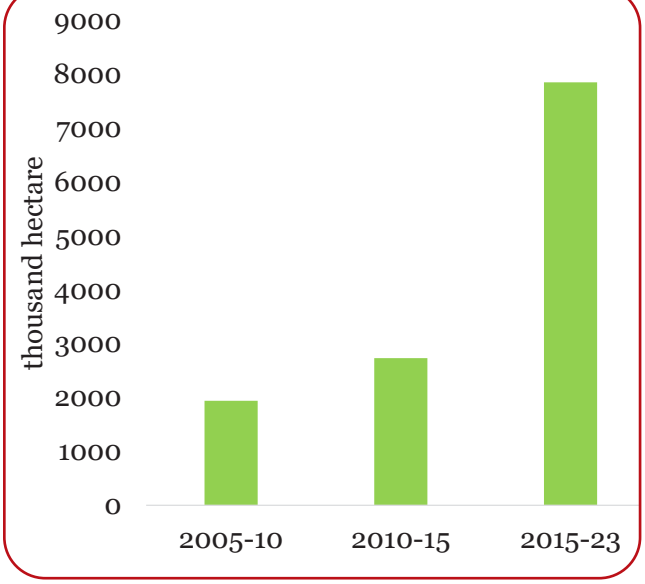

संधारणीय खेती को प्रोत्साहन देना: प्रमुख उपाय

10 जलवायु और पर्यावरण: अनुकूलन की अनिवार्यता

भारत के लिए चुनौतियां और प्राथमिकताएं

चुनौतियां

- वर्ष 2047 तक एक विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने और वर्ष 2070 तक निवल शून्य बनने के लिए उच्च आर्थिक विकास।
- वित्त और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अत्यंत अपर्याप्त है। भारत अपनी आवश्यकताओं को अधिकतर अपने स्वयं के बजटीय स्रोतों से पूरा करता है। 300 अरब अमेरिकी डॉलर का एक छोटा एनसीक्यूजी निर्धारित किया गया है।
- नवीकरणीय ऊर्जा की सीमा को देखते हुए सभी के लिए रोजगार सृजन और किफायती ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निम्न कार्बन वाले विकास की राह का पालन करना।

प्राथमिकताएं

- जलवायु परिवर्तन की उच्च संवेदनशीलता को देखते हुए अनुकूलन को सबसे आगे लाना।
- सुपर-क्रिटिकल (एससी), अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल (यूएससी) और एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से अपनी अपरिहार्य तापीय ऊर्जा की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना।
- मिशन एलआईएफई के तहत परिकल्पित उपभोग और उत्पादन के व्यवहार के माध्यम से पर्यावरणीय संधारणीयता पर भी ध्यान केंद्रित करना।

निधियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में शमन पूर्वाग्रह

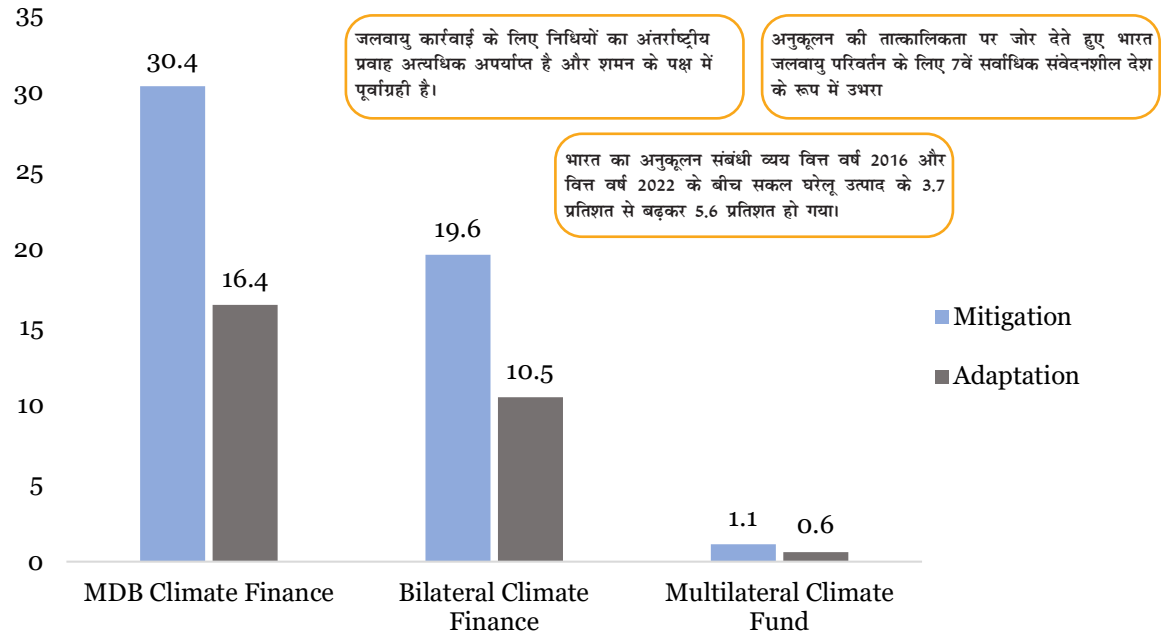

भारत की एनडीसी की ओर प्रगति

नवीकरणीय ऊर्जा

वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत के अद्यतन एनडीसी लक्ष्य की तुलना में, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 30 नवंबर, 2024 तक 46.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

वन क्षेत्र

भारत के नवीनतम वन सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन सीओ2 के समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के एनडीसी लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2005 और वर्ष 2023 के बीच 2.29 बिलियन टन सीओ2 के समत. ुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है।

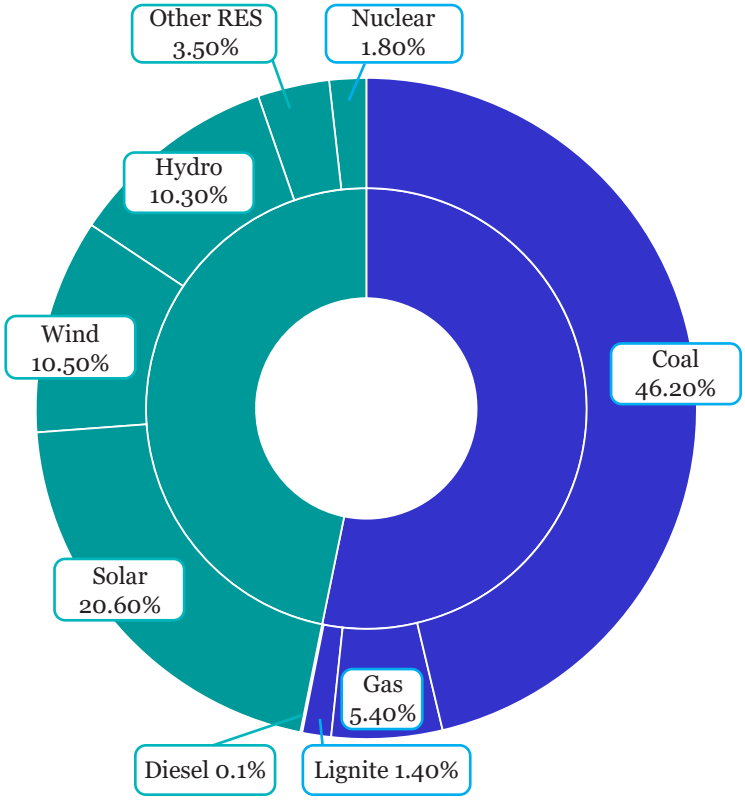

जलवायु संबंधी पहल

अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर भारत की उपलब्धियों का श्रेय नवीकरणीय ऊर्जा और हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं, नीतियों, वित्तीय प्रोत्साहन और विनियामक उपायों को दिया जाता है।

पर्यावरण के लिए जीवन शैली (एलआईएफई): पर्यावरण के लिए सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग करना

सामूहिक कार्रवाई की शक्ति

- वैश्विक आबादी का 13 प्रतिशत जीवन शैली परिवर्तन कार्बन उत्सर्जन को 20 प्रतिशत तक कम कर सकता है।
- थाली में परोसे गए भोजन को पूर्ण रूप से उपभोग करने से प्रति व्यक्त 90 किलोग्राम वार्षिक भोजन की बर्बादी से बचा जा सकता है।
- कारपूल भारत में प्रतिदिन 7,80,000 सवारी करने से 380 मिलियन लीटर ईंधन की बचत कम कर सकता है।
- 1 टन समाचार पत्र के पुनर्चक्रण से 25,000 लीटर पानी की बर्बादी से बचा जा सकता है।

11 सामाजिक क्षेत्र: पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन

सामाजिक सेवा व्यय में वृद्धि (संघ+राज्य)

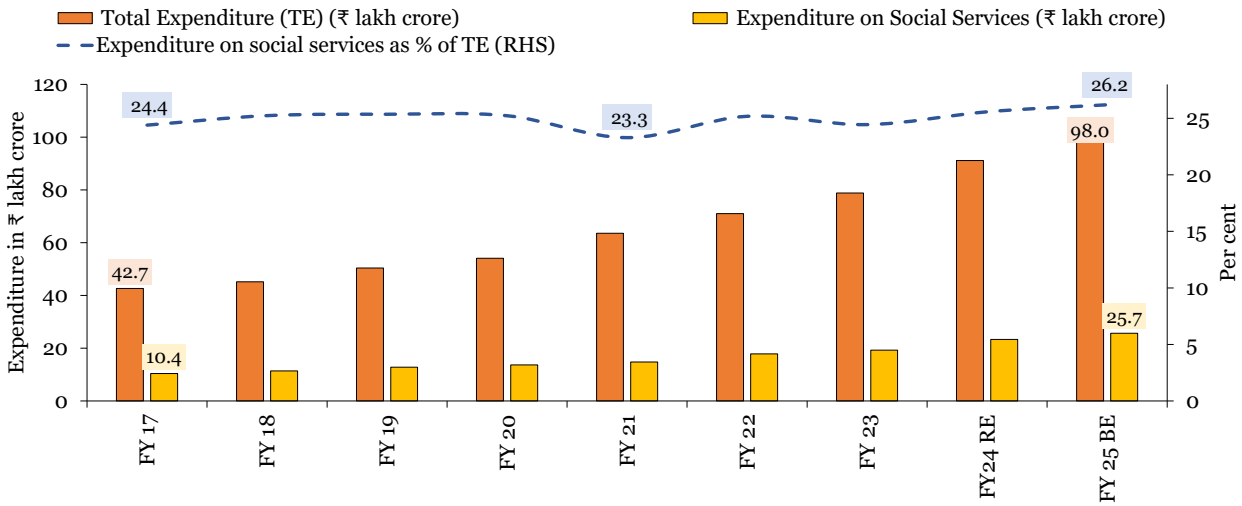

टिप्पणी : शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 22 (बीई) में शिक्षा पर कुल रुपये 9.7 लाख करोड़ व्यय किया गया।

आजीवन पढ़ने के लिए मजबूत नींव का निर्माण

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार

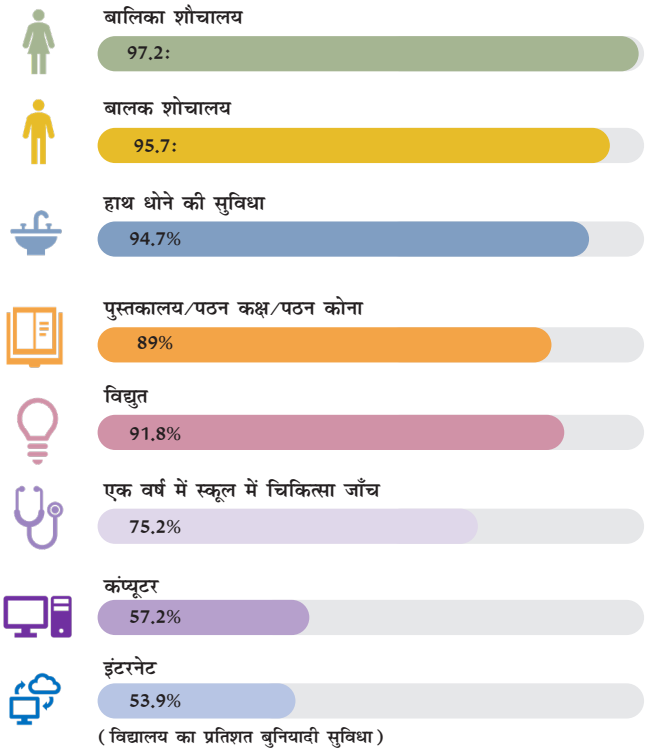

(विद्यालय का प्रतिशत बुनियादी सुविधा)

बेहतर शिक्षा के लिए बिल्डिंग ब्लॉक

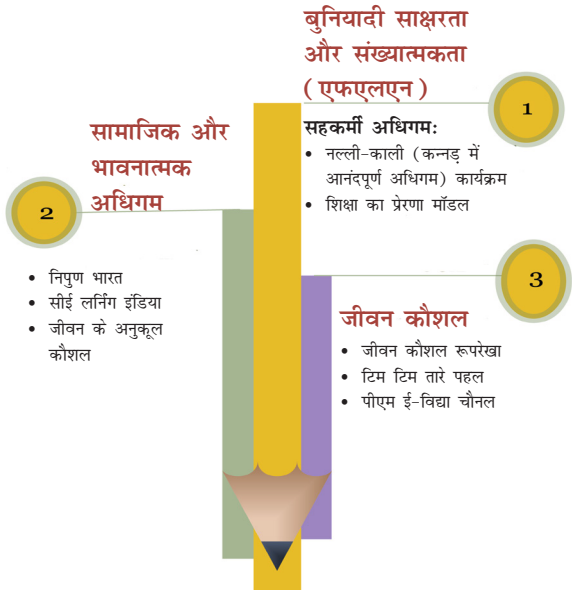

स्रोत : यूडीआईएसई + 2023-24

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
11.8 करोड़ शौचालय और 2.51 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया।

मिशन अमृत सरोवर
68,843 तालाबों का निर्माण किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - ग्रामीण
165.6k उप-केंद्र (एससी)
25.4k प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)
5.5k सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)
सांसदों द्वारा गोद ली गई 3,361 ग्राम पंचायतें (जीपी)

जल जीवन मिशन
12.2 करोड़ घरों को नल के जरिए जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)
2.69 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
7,70,983 किलोमीटर सड़क लंबाई पूरी हो गई।

सबके लिए स्वास्थ्य

किफायती औषधि और टीकाकरण

14000 से अधिक जन औषधि केंद्र

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर 93.5 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य बीमा और देखभाल का निर्माण

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं।

1,75,560 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए गए, जिनमें 370 करोड़ से अधिक लोग आए।

डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी निर्बाध और उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है।

72.81 करोड़ एबीएचए पहचान पत्र बनाए गए।

यू-डब्ल्यूआईएन के अधीन 1.7 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 5.4 करोड़ बच्चों पर नजर रखी गई; 26.4 करोड़ टीके की खुराक की निगरानी की गई।

ई-संजीवनी: 31.19 करोड़ रोगियों सेवा से लाभान्वित हैं।

टिप्पणी : नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार।

12

रोजगार और कौशल विकास: अस्तित्वगत प्राथमिकताएं

श्रम बाजार संकेतकों में सुधार

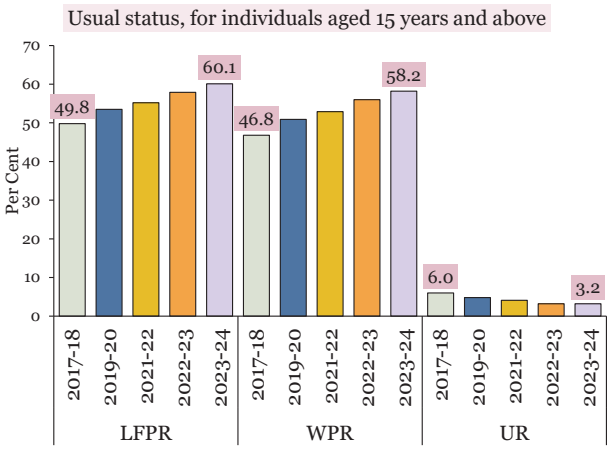

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ।

नोट: एलएफपीआर: श्रम बल भागीदारी दर

यूआर: बेरोजगारी दर यूआर: बेरोजगारी दर

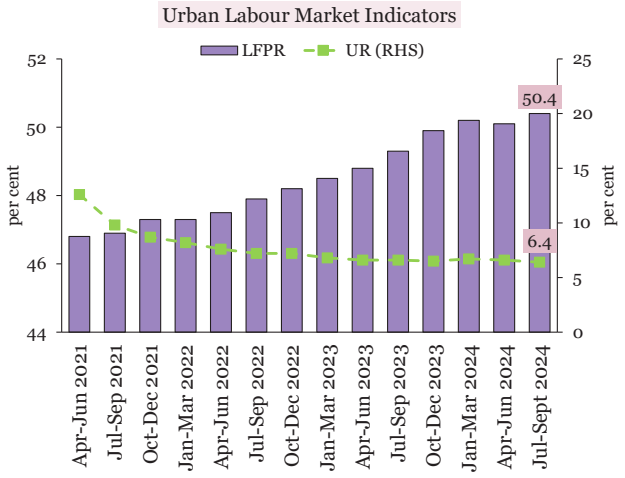

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तिमाही रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि

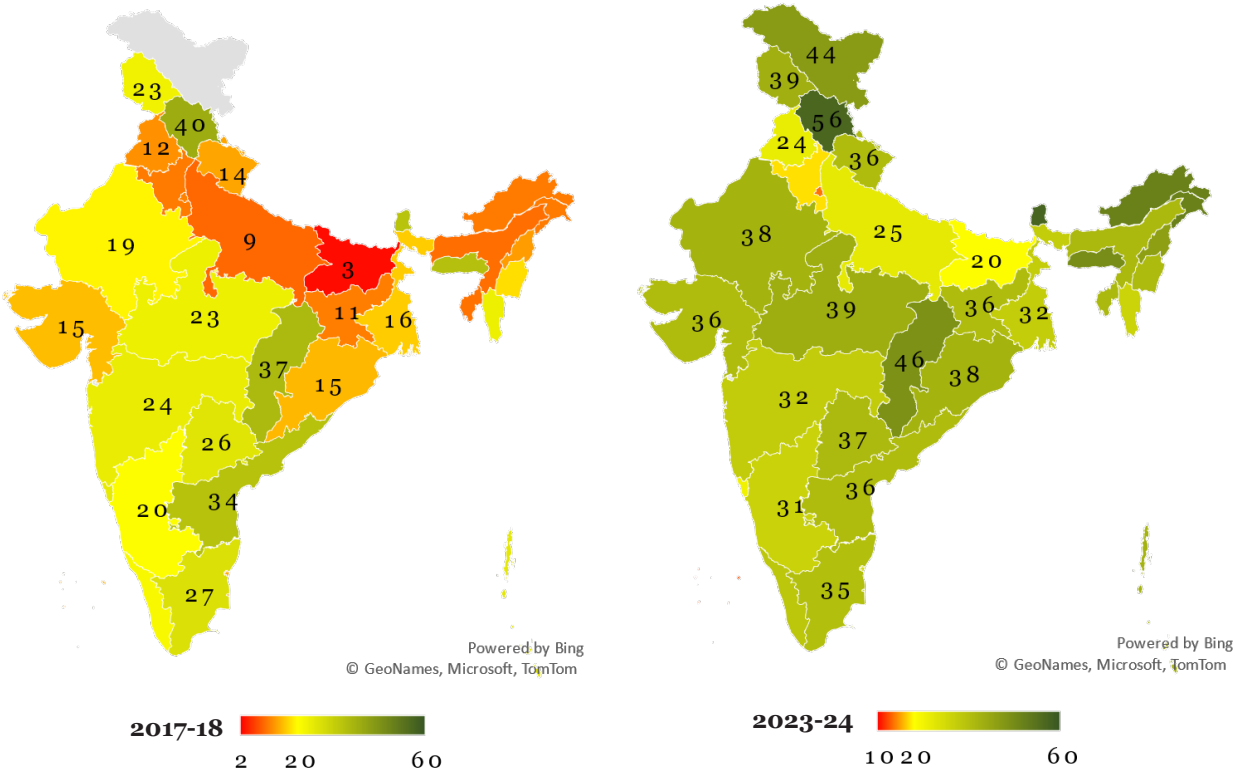

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ाना

महिला उद्यमियों की शक्ति का उपयोग करना

कौशल विकास
- एसएएनकेएलपी (संकल्प)
- कॉयर विकास
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि

ऋण सहायता
- क्रेडिट गारंटी योजना
- स्टार्ट-अप समर्थन
- प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना
- आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना
- एनसीडीसी सहायता

विपणन सहायता
पूर्णत: सब्सिडी वाले व्यापार मेले
भागीदारी

महिला स्वामित्व वाले उद्यमों को समर्थन
- औपचारिकता
- सीपीएसई द्वारा प्रापण का 3% आरक्षित
- पूर्णत: सब्सिडी वाला जेड प्रमाणन

रोजगार के अवसर को आगे बढ़ाना

रोजगार सृजन के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था का उपयोग करना

वर्ष 2025 तक भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान है।

हरित कार्यबल का निर्माण

वर्ष 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के 1.02 मिलियन अनुमानित स्तर पर पहुंचा।

वर्ष 2029-30 तक गिग कार्य बल के 2.35 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।

हाइड्रोपावर, भारतीय नवीकरणीय क्षेत्र में 4, 53, 000 रोजगार सृजित करके पूरे विश्व में वैश्विक रोजगार का 20% योगदान करता है।

बदलती दुनिया हेतु कौशल

पुनर्कौशल एवं अपस्किलिंग

- **आईटीआई में सीटीएस:** 1.24 करोड़ ने दीर्घावधिक प्रशिक्षण के लिए नामांकन कराया।
- **पीएमकेवीवाई:** 1.57 करोड़ प्रशिक्षित; 1.21 करोड़ प्रमाणित (एसटीटी, एसपी, आरपीएल)।
- **जेएसएस:** 27 लाख प्रशिक्षित; 26 लाख प्रमाणित।

महिलाओं की सहभागिता

- **पीएमकेवीवाई:** महिलाओं की सहभागिता 58% (वित्त वर्ष 25) है।
- **पजेएसएस:** कुल लाभार्थियों में महिलाओं की सहभागिता 82% है।
- **आईटीआई/एनएसटीआई:** महिलाओं की सहभागिता 9.8% (वित्त वर्ष 16) से बढ़कर 13.3% (वित्त वर्ष 24) हो गई।
- **एनएपीएस:** महिलाओं की हिस्सेदारी 7.7% (वित्त वर्ष 17) से बढ़कर 22.8% (वित्त वर्ष 25) हो गई।

अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता

- द्विपक्षीय साझेदारी
- जी2जी समझौता ज्ञापन
- कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
- प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण

नये युग एवं भविष्य के कौशल

- **एनसीवीईटी:** अनुमोदित 200+ नए युग और भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम।
- **पीएमकेवीवाई:** 4.65 लाख नामांकित; 3.02 लाख प्रशिक्षण पूर्ण किया; 98 हजार प्रशिक्षणरत है
- **आईटीआई:** सीटीएस के तहत 29 नए युग के पाठ्यक्रम जोड़े गए।

उद्योग साझेदारी

- **एनएपीएस पोर्टल:** पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या 2.38 लाख तक पहुँच गई; नियुक्त प्रशिक्षु 37.94 लाख
- नई आईटीआई उन्नयन योजना (2024): हब-एंड-स्पोक में 1,000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा।
- 20 लाख युवाओं को उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रमों में 5 वर्षों में प्रशिक्षित किया जाएगा

कौशल विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

- **स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल:** कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी मंच।
- **कौशल का लोकतंत्रीकरण:** उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रमों तक सुगम्य।

टिप्पणी : नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार।

13 एआई युग में श्रम व्यवस्था : संकट या उत्प्रेरक

मानव-केंद्रित स्वचालन का भविष्य

- श्रम-समृद्ध भारत के लिए एआई का उपयोग अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है
- अतीत में हुई प्रौद्योगिकीय क्रांतियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन नहीं किए जाने की स्थिति में वे दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभावों सहित कष्टकारी रही हैं।
- भारत के श्रम बाजारों के जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत सक्षम, बीमाकरण और प्रबंधनकारी संस्थानों की आवश्यकता है
- लंबे समयकाल तक अनुकूलित सावधानीपूर्ण परिनियोजन यह सुनिश्चित कर सकता है कि एआई श्रम को बढ़ावा दे और व्यापकता-आधारित सामाजिक हितलाभ प्रदान करे
- सरकार, निजी क्षेत्र और अकादमिक जगत के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि भविष्य में काम का ऐसा माहौल बने जिसमें एआई 'श्रम प्रतिस्थापक' के बजाय 'श्रम संवर्धक' बन सके।

एआई के स्केल निर्धारण संबंधी चुनौतियाँ

व्यावहार्यता

सफलताओं को व्यावहारिक, व्यापक रूप से अपनाए गए अनुप्रयोगों में परिवर्तित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि एआई वर्तमान में

प्रयोगात्मक और असमान उपयो. गिता को दर्शाता है

विश्वसनीयता

वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए एआई की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वायत्त संवाहकों या स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख उद्योगों में विफलताएँ समस्या बढ़ाने वाली साबित हो सकती हैं

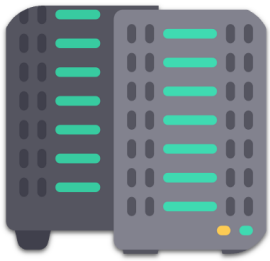

अवसंरचना

बड़े पैमाने पर एआई से संबंधित अवसंरचना में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें डाटा सेंटर, डाटा को क्लीन करने संबंधी पाइपला. इन और कम्प्यूटेशनल संसाधन शामिल हैं

संसाधन

बड़े मॉडल सघन संसाधन युक्त होते हैं, जिनमें उच्च ऊर्जा खपत, हार्डवेयर और वित्तपोषण के लिए दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता की आवश्यकता होती है, जिससे संधारणीय नवाचार आवश्यक हो जाता है

सत्यमेव जयते
Government of India

आर्थिक कार्य विभाग
DEPARTMENT OF
ECONOMIC AFFAIRS